A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 21 फरवरी, 2026

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 171, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

रोबोडॉग से रिसर्च पेपर तक : संकट में वैज्ञानिक ईमानदारी?

शीतल पी. सिंह

रोबोडॉग प्रोजेक्ट से लेकर शोध पत्रों तक प्लेजरिज़्म के आरोपों ने वैज्ञानिक ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या अकादमिक संस्थानों में रिसर्च की गुणवत्ता और नैतिकता संकट में है?

2026 के 'इंडिया एआई इंपैक्ट समिट' में जो कुछ हुआ, वह किसी एक विश्वविद्यालय या एक प्रोफेसर की भूल भर नहीं था। यह उस बीमारी का ताज़ा लक्षण था, जो पिछले एक-दो दशक से भारतीय अकादमिक और शोध संस्थानों को भीतर से खोखला कर रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा मंच पर 'इन-हाउस इनोवेशन' बताकर दिखाया गया रोबोट डॉग–जिसे 'ओरियन' नाम दिया गया–असल में चीन की nitree Robotics का रेडी-मेड कमर्शियल मॉडल निकला। यह घटना सिर्फ एक 'फेक डेमो' नहीं थी; यह बताती है कि कैसे प्लेजरिज्म और मिसरिप्रेजेंटेशन अब प्रयोगशालाओं से निकलकर पब्लिक स्पेस और राष्ट्रीय आयोजनों तक पहुंच चुके हैं।

इनोवेशन का दिखावा, सच्चाई का अभाव– किसी विदेशी कंपनी का उत्पाद खरीदकर उसे अपना बताना–और वह भी राष्ट्रीय मंच पर–दोहरी समस्या को उजागर करता है। पहली, संस्थागत सत्यापन की कमी; दूसरी, उस संस्कृति का सामान्यीकरण जिसमें 'दिखना' ज़्यादा अहम है, 'होना' नहीं। जब प्रोफेसर टीवी कैमरे के सामने बिना जाँच-पड़ताल के ऐसे दावे करते हैं, तो सवाल सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता का नहीं रहता–यह पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर चोट है।

चीनी मीडिया ने इस प्रकरण को 'embarrassing plagiarism' कहा। यह तंज नहीं, चेतावनी है। क्योंकि जब हम तकनीकी आत्मनिर्भरता का दावा करते हैं और मंच पर खरीदी हुई मशीन को 'स्वदेशी नवाचार' बताकर पेश करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय भरोसा टूटता है।

परेशान करने वाला ट्रैक रिकॉर्डः भारत में प्लेजरिज्म और रिसर्च मिसकंडक्ट का इतिहास छोटा नहीं है। अकादमिक जगत में PubPeer जैसे प्लेटफॉर्म पर भारतीय शोधकर्ताओं के सैकड़ों पेपरों पर सवाल उठे हैं–इमेज डुप्लिकेशन, डेटा मैनिपुलेशन, फिगर री-यूज़ जैसे आरोप आम हो चुके हैं। कई मामलों में जर्नल्स को पेपर वापस लेने पड़े, लेकिन संस्थागत कार्रवाई या तो हुई ही नहीं, या बहुत हल्की रही।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और वाइस चांसलर रहे अविनाश चंद्र पांडे के दर्जनों पेपरों पर सवाल उठे; कुछ रिट्रैक्ट भी हुए। इसके बावजूद वे आज भी प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हैं। यही पैटर्न अन्य नामों में भी दिखता है–IIT धनबाद, पेरियार यूनिवर्सिटी, और Saveetha Institute से जुड़े शोधकर्ताओं के बड़े पैमाने पर रिट्रैक्शन इसका उदाहरण हैं।

CSIR और 'राष्ट्रीय प्रतिष्ठा' का भ्रमः कभी-कभी तर्क दिया जाता है कि 'ये तो इक्का-दुक्का मामले हैं।' लेकिन जब CSIR जैसी शीर्ष संस्था की लैब्स से जुड़े सैकड़ों पेपरों पर सवाल उठते हैं तो यह तर्क ढह जाता है। 2019 में ही 100 से अधिक पेपर रिट्रैक्ट हुए; 2023 तक यह संख्या हज़ारों में पहुंच गई। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं–यह उस शोध संस्कृति का आईना है जिसमें आउटपुट की संख्या गुणवत्ता से ऊपर रख दी गई।

पूर्व CSIR वैज्ञानिक अशोक पांडे के दर्जनों पेपरों का रिट्रैक्ट होना, एडिटोरियल मिसकंडक्ट के आरोप–ये सब बताते हैं कि समस्या 'जूनियर बनाम सीनियर' की नहीं है। यहां पद, पुरस्कार और नेटवर्क कई बार जवाबदेही से ढाल बन जाते हैं।

बड़े नाम भी नहीं बचेः प्लेजरिज्म का मुद्दा तब और गंभीर हो जाता है जब देश के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में शुमार नाम भी घेरे में आते हैं। आर. ए. माशेलकर–CSIR के पूर्व प्रमुख और पद्म विभूषण सम्मानित–पर 2007 में पेटेंट कानून पर तैयार रिपोर्ट में प्लेजरिज्म के आरोप लगे। रिपोर्ट वापस ली गई; उन्होंने 'अनजाने में हुई गलतियों' की बात कही। लेकिन सवाल यह हैः जब शीर्ष स्तर पर भी परिणाम इतने सीमित हों, तो नीचे तक क्या संदेश जाता है? The Times of India जैसी मुख्यधारा मीडिया में यह खबर छपी, बहस हुई–पर संरचनात्मक सुधार नहीं हुए।

दबाव का दुष्चक्रः भारत में इस प्रवृत्ति के पीछे सबसे बड़ा कारण वही है जिसे अकादमिक दुनिया 'Publish or Perish' कहती है। प्रमोशन, ग्रांट, रैंकिंग–सब कुछ पेपरों की संख्या से जोड़ा गया। गुणवत्ता की जांच के लिए समय, संसाधन और इच्छाशक्ति–तीनों की कमी रही। परिणामस्वरूपः

जल्दबाज़ी में शोधः पर्याप्त रिप्लिकेशन या वेरिफिकेशन के बिना निष्कर्ष।

इमेज और डेटा मैनिपुलेशनः क्योंकि 'पॉज़िटिव रिज़ल्ट' चाहिए।

पेपर मिल्स का उदयः पैसे देकर तैयार पांडुलिपियाँ।

संस्थागत चुप्पीः शिकायत आए तो 'आंतरिक समिति' बनाकर मामला ठंडे बस्ते में।

गलगोटिया का रोबोडॉग दिखाता है कि यही मानसिकता अब 'इन्वेंशन' के दावों तक फैल चुकी है–खरीदो, नाम बदलो, तालियाँ बटोर लो।

अंतरराष्ट्रीय छवि और घरेलू नुकसानः इसका असर सिर्फ प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभावित होते हैं–विदेशी यूनिवर्सिटीज़ और फंडिंग एजेंसियाँ सावधान हो जाती हैं। घरेलू प्रतिभा का मनोबल टूटता है–ईमानदारी से काम करने वाले शोधकर्ता हाशिये पर चले जाते हैं। नीतिगत फैसले कमजोर होते हैं–जब वैज्ञानिक सलाह संदिग्ध डेटा पर आधारित हो।

क्या किया जाए?ः कठोर और स्वतंत्र जांचः संस्थानों से स्वतंत्र राष्ट्रीय रिसर्च इंटेग्रिटी अथॉरिटी, जिसके फैसले बाध्यकारी हों।

दंड का वास्तविक अर्थः रिट्रैक्शन के साथ पद, ग्रांट और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर असर।

मेट्रिक्स का सुधारः संख्या नहीं, पुनरुत्पादकता (reproducibility) और ओपन डेटा को महत्व।

व्हिसलब्लोअर संरक्षणः शिकायत करने वालों को सुरक्षा, न कि प्रताड़ना।

पब्लिक डेमो में सत्यापनः 'इन-हाउस इनोवेशन' के दावों के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट।

क्या कोई सबक लेंगे?ः रोबोडॉग प्रकरण एक आईना है–हम चाहें तो उसमें खुद को देखकर सुधार कर सकते हैं, या फिर आईना तोड़ सकते हैं। सवाल यह नहीं कि गलतियाँ हुईं; सवाल यह है कि क्या हम उन्हें स्वीकार कर सुधारेंगे?

अगर नहीं, तो 'वैश्विक ज्ञान शक्ति' बनने का सपना खोखला रहेगा–तालियों की आवाज़ में सच्चाई दबती रहेगी, और अगला रोबोडॉग फिर किसी मंच पर मुस्कुराता हुआ खड़ा होगा।

सबक साफ हैः विज्ञान में शॉर्टकट नहीं चलते। ईमानदारी ही असली इनोवेशन है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

बदन पे जिस के शराफ़त का पैरहन देखा
वो आदमी भी यहाँ हम ने बद–चलन देखा
ख़रीदने को जिसे कम थी दौलत–ए–दुनिया
किसी कबीर की मुट्ठी में वो रतन देखा
मुझे मिला है वहाँ अपना ही बदन ज़ख्मी
कहीं जो तीर से घायल कोई हिरन देखा
बड़ा न छोटा कोई फ़र्क़ बस नज़र का है
सभी पे चलते समय एक सा कफ़न देखा
ज़बाँ है और बयाँ और उस का मतलब और
अजीब आज की दुनिया का व्याकरन देखा
लुटेरे डाकू भी अपने पे नाज़ करने लगे
उन्होंने आज जो संतों का आचरन देखा
जो सादगी है कुहन में हमारे ऐ 'नीरज'
किसी पे और भी क्या ऐसा बाँकपन देखा ।

- गोपालदास नीरज

इंदौर के भागीरथपुरा मामले पर विधानसभा में नहीं होगी चर्चा

● स्पीकर बोले- ये नियम के खिलाफ, पहले बात हो चुकी; विपक्ष ने कहा-जवाबदेही से भाग रहे

बजट सत्र के पांचवें दिन भी पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस

भोपाल (नप्र)। बजट सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को विधानसभा में इंदौर में दूषित पानी से मौतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि घटना के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। पीड़ितों के इलाज, पानी की जांच और नई पाइपलाइन का काम शुरू किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने कहा कि यह 90 साल पुरानी बस्ती है। यहां अशिक्षित लोग रहते हैं, जहां काम करना नगर निगम कर्मचारियों के लिए मुश्किल होता है। इसी कारण नगर निगम के कर्मचारी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। महापौर ने टेंडर जारी किए थे, लेकिन काम समय पर शुरू नहीं हो पाया।

इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लोगों को साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है। काला पानी की सजा तो सुनी है, लेकिन यहां तो लोगों को काला पानी पिलाया जा रहा है। इस पर सरकार जवाब नहीं दे रही है।

विपक्ष ने इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की तो स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- विधानसभा की नियमावली के नियम 55 के उपखंड 5 के अनुसार स्थगन प्रस्ताव में उस विषय पर चर्चा नहीं होगी, जिस पर सदन में पहले ही चर्चा हो चुकी है।

विजयवर्गीय और शेखावत ने ली चुटकी

प्रश्नकाल के दौरान विधायक भंवर सिंह शेखावत ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर हास्यपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा- आज कैलाश जी बदले-बदले नजर आ रहे हैं।

नहीं होगी चर्चा, स्पीकर ने नियम बताया– भागीरथपुरा में प्रदूषित पानी से मौतों पर स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा– स्थगन प्रस्ताव के विषय में माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है। इस पर बारीकी से सोचने–विचारने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विधानसभा की नियमावली के नियम 55 के उपखंड 5 के अनुसार स्थगन प्रस्ताव में उस विषय पर चर्चा नहीं होगी, जिस पर सदन में चर्चा हो चुकी है।

कांग्रेस विधायक ने कहा– विजयवर्गीय सीएम बन जाएंगे तो सांदिपनी विद्यालय से कैलाश विद्यालय बन जाएंगे– बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा– आप वित्तीय प्रबंधन के लिए 33 हजार करोड़ रुपए तो ब्याज में दे रहे हैं। डिंडौरी जिले में 54 करोड़ मजदूरी चार महीने से पेंडिंग है। उन्होंने कहा– सरकारी स्कूलों के बार–बार नाम बदले जा रहे हैं। अब विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सांदिपनी विद्यालय से कैलाश विद्यालय बन जाएंगे। हमारी आयु निश्चित है तो हम भविष्य को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? मेरा अनुरोध है कि आज स्कूलों की हालत बहुत खराब है। भवन उपयुक्त नहीं हैं। पीने का पानी, खेल के मैदान का प्रबंध नहीं है। किसानों को भी सरकार न्याय नहीं दे पा रही है।

भूख से तड़प-तड़पकर मरा बूढ़ा तेंदुआ

20 दिन बाद पता चला
पहाड़ पर मिलीं सिर्फ हड्डियां

देवास (नप्र)। जिले के खातेगांव तहसील के विक्रमपुर-सागोनिया के जंगल में एक पहाड़ी पर करीब 20 दिन पुराना एक नर तेंदुए का कंकाल मिला है। एक किसान ने खेत में बंदर भगाते समय बदबू आने पर इस मृत तेंदुए को देखा और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पशु चिकित्सक ने प्रथम दृष्टया तेंदुए की मौत भूख से होने की आशंका जताई है, क्योंकि वह वृद्ध होने के कारण शिकार करने में असमर्थ था।

14 साल का था नर तेंदुआ

पशु चिकित्सक चिरंजीव चौहान ने बताया कि यह नर तेंदुआ करीब 14 साल का था। प्रथम दृष्टया, यह माना जा रहा है कि वह बूढ़ा होने के कारण शिकार नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते भूख से उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने तेंदुए के शव के सैंपल एकत्र कर लिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण पता चलेगा।

जबलपुर के पास आरती-अजान के विवाद में बवाल

● मंदिर से घसीटकर पीटने के आरोप, पथराव के बाद 49 गिरफ्तार, कर्फ्यू जैसे हालात

पुलिस का पहरा, छतों से हो रही निगरानी, मंदिर में मां की हुई पूजा

जबलपुर/सीहोरा (नप्र)। मध्यप्रदेश के जबलपुर से करीब 40 किमी दूर सिहोरा तहसील में गुरुवार रात दुर्गा मंदिर और मस्जिद के बीच आरती-अजान को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पथराव और मारपीट के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। सिहोरा में गुरुवार की रात में सांप्रदायिक हिसंक टकराव होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र पुलिस छावनी बना हुआ है। क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और वह सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। सांप्रदायिक तनाव के कारण शुक्रवार को क्षेत्र की दुकानें बंद रही है।

भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है।

कैसे शुरू हुआ विवाद

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान एक ही समय पर हो रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और मामला झड़प तक पहुंच गया। आरोप है कि मस्जिद से 50-70 युवकों की भीड़ बाहर आई और विवाद बढ़ गया।

पुलिस छावनी में तब्दील है इलाका

सुरक्षा की दृष्टि से शुक्रवार को भी क्षेत्र पुलिस छावनी बना हुआ है। हिंसक टकराव के बाद क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रही और पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रखी हुई है।

पुलिस अनावश्यक रूप से लोगों को क्षेत्र में रुकने नहीं दे रही है। लोगों का हुजूम एकत्र नहीं हो पाए। इस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पुलिस ड्रोन के माध्यम से लोगों की छतों पर नजर रख रही है।

मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप

दुर्गा मंदिर समिति के सदस्य अंकेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि भीड़ ने मंदिर में घुसने की कोशिश की और उन्हें अंदर से घसीटकर बाहर निकाला गया। उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद 20-25 मिनट तक पथराव चलता रहा, जिसमें मंदिर के कांच टूट गए और कई लोग घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया।

22 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने गुरुवार को देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लेटर लिखकर एसआईआर से जुड़ी तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने लेटर में बताया कि दिल्ली, कर्नाटक सहित शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। लेटर में आगे कहा गया है कि चुनाव आयोग ने पिछले साल 24 जून को आदेश दिया था कि पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने पहले फेज में बिहार में एसआईआर करवाया था। दूसरे फेज के तहत, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2025 से एसआईआर जारी है। असम में, एसआईआर के बजाय स्पेशल रिवीजन 10 फरवरी को पूरा किया गया था। दूसरे फेज के तहत, नौ राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2025 से एसआईआर शुरू हुआ था।

बंगाल में एसआईआर की निगरानी करेंगे न्यायिक अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, ममता बनर्जी की खिंचाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार और इलेक्शन कमिशन के बीच चल रहे विवाद को लेकर आपत्ति जताई। इसके साथ ही अदालत ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि वह न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करे। अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर चल रहे अभियान पर जिस तरह का विवाद राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, एक-दूसरे पर आरोप लगाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि दोनों संवैधानिक निकायों के बीच आपस में कोई भरोसा नहीं है। ये दोनों राज्य सरकार और चुनाव आयोग हैं। फिलहाल प्रक्रिया इस बात के बीच फंसी हुई है कि कुछ लोगों को आपत्ति है और कुछ लोगों का कहना है कि वोटर लिस्ट से गलत ढंग से नाम हटाए गए हैं।

● **चीफ जस्टिस बोले- ऐसे हालात पैदा हो गए कि हमें दखल देना पड़ रहा**

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि न्यायिक अधिकारियों को दखल देना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस मामले में सहयोग करे। क्या राज्य सरकार की ओर से इस तरह पक्ष रखना चाहिए। बेंच ने कहा कि 9 फरवरी को होने वाली सुनवाई के लिए जो तथ्य रखे जाने थे, वे 17 तारीख को रखे गए। आप कह रहे हैं कि अधिकारियों का परीक्षण हो रहा है। आखिर यह प्रक्रिया है और इसमें कितना समय लगता है। बेंच ने कहा कि हम यह सब देखकर निराश हुए हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 21 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

19 साल बाद भारत में परफॉर्म करेंगी ग्लोबल स्टार शकीरा

● अप्रैल में मुंबई और दिल्ली में ग्रैमी अवॉर्ड विनर के लाइव शो होंगे

मुंबई (एजेंसी)। ग्लोबल पॉप स्टार और कई ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुकीं सिंगर शकीरा अप्रैल में 19 साल बाद भारत में परफॉर्म करेंगी। वह 10 अप्रैल को मुंबई और 15 अप्रैल को दिल्ली में लाइव शो करेंगी। यह जानकारी फीडिंग इंडिया और डिस्ट्रिक्ट बाय जौमैटो ने दी। फीडिंग इंडिया एक नॉन-प्रॉफिट संस्था है, जो भूख और कुपोषण के मुद्दों पर काम करती है। बता दें कि शकीरा ने आखिरी बार

भारत में 2007 में मुंबई में ओरल फिक्सेशन टूर के दौरान परफॉर्म किया था। आयोजकों के अनुसार, कॉन्सर्ट का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भूख और कुपोषण जैसे मुद्दों पर जागरुकता बढ़ाना भी है। शकीरा मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म करेंगी। एक प्रेस नोट में शकीरा ने कहा, भारत में परफॉर्म करना मेरे लिए हमेशा खास रहा है। मैं मुंबई और दिल्ली के फैंस से मिलने के लिए उत्साहित हूं। फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट सिर्फ म्यूजिक नहीं, बल्कि बच्चों के पोषण के लिए साथ खड़े होने का संदेश है।

हिंदी लेखिका संघ का वार्षिक उत्सव एवं कृति पुरस्कार समारोह 22 को

भोपाल। हिन्दी लेखिका संघ, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा 31वां वार्षिक उत्सव एवं कृति पुरस्कार-सम्मान समारोह 22 फरवरी रविवार को प्रातः 11 बजे पं. रविशंकर सभागृह, हिन्दी भवन, पॉलीटेक्निक चौराहा, भोपाल में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 'सर्जना स्मारिका' का लोकार्पण भी होगा। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यकांत नागर (इंदौर) होंगे। प्रमुख अतिथि डॉ. संतोष चौबे, कुलाधिपति, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल एवं निदेशक, विश्वरंग रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. करुणा सक्सेना, प्रांत मंत्री, मध्यभारत, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, ग्वालियर करेंगी। इस अवसर पर विभिन्न प्रतिष्ठित सम्मानों में कुसुम कुमारी जैन वरिष्ठता सम्मान, डॉ. फिरोजा मुजफ्फर सेवा सम्मान, डॉ. सुशीला कपूर हिंदी सेवी सम्मान तथा श्रीमती शोभा शर्मा कर्मठता सम्मान प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही कृति पुरस्कार विभिन्न विधाओं—समग्र साहित्य, उपन्यास, ग़ज़ल, नाटक, लघुकथा, कथा, लोक साहित्य, बाल कविता, आध्यात्मिक पद्य, डायरी एवं समीक्षा में प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित अन्य शहरों के साहित्यकारों को उनकी उल्लेखनीय कृतियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में मीडिया जगत सम्मान के अंतर्गत मनीष गौतम, सुश्री निधि सिंह, सुबीर तिवारी, सुशील पांडे तथा सुश्री अमिता त्रिवेदी को भी सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी संघ की प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. साधना गंगराड़े ने दी।

विक्रमोत्सव 2026

'जाति जीवनम्' में नैतिक उत्तरदायित्व की प्रस्तुति

(उज्जैन से डॉ. जफर महमूद)

उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव के नाट्य समारोह की चतुर्थ संध्या ओडिशा के नाट्य निर्देशक चित्तरंजन सत्पथी के निर्देशन में नाटक जाति जीवनम् का रंजक मंचन हुआ। यह पौराणिक कथा पर आधारित चरित्र-प्रधान एकांकी नाटक था। प्रसिद्ध कथाकार महामहोपाध्याय पंडित गोविन्द चन्द्र मिश्र रचित इस नाटक ने जातिगत भेदभाव, वंश-रक्षा और नैतिक उत्तरदायित्व जैसे विषयों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नाटक में ओडिशा के द क्याज, नाट्य समूह के कला दल द्वारा प्रभावी अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। भारतीय पौराणिक परंपरा पर आधारित इस एकांकी में जातीय चेतना, वंश-संरक्षण और नैतिक दायित्वों की गंभीर अभिव्यक्ति देखने को मिली। नाटक के भावपूर्ण प्रसंगों और वैचारिक गहराई ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। कथानक ऋषि जरत्कारु के उस सशर्त विवाह-संकल्प के इर्द-गिर्द विकसित होता है, जिसे वे पितृ-पुरुषों द्वारा सौंपे गए वंश-रक्षा के दायित्व के निर्वहन हेतु स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर नागयज्ञ के माध्यम से नागजाति के विनाश की प्रतिज्ञा लेते हैं। विषम परिस्थिति में वासुकि की भगिनी नागजाति की रक्षा के लिए स्वयं को उत्सर्ग करने का संकल्प लेती है। नाटक में करुणा और आत्मबलिदान की चरम संवेदना को प्रकट किया गया। नाटक के माध्यम से निस्वार्थ समर्पण, निष्काम कर्तव्यबोध और सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रभावी संदेश दिया गया। नाटक में ओडिशा के कलाकारों ने प्रभावपूर्ण अभिनय क्षमता का परिचय दिया।

कांग्रेस ने सीमाएं खुली छोड़ीं इसलिए घुसपैठ बढ़ी

● अमित शाह बोले-5 साल में राज्य को बाढ़मुक्त करेंगे

शाह ने असम से 6900 करोड़ की योजना लॉन्च की

दिसपुर (एजेंसी)। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने देश की सीमाएं खुली छोड़ दी थीं, जिसकी वजह से असम में घुसपैठ बढ़ी। भाजपा सरकार ने इस समस्या से सख्ती से निपटा है। शाह ने असम के कछार जिले में जनसभा में कहा कि कांग्रेस के शासन में असम में कोई विकास कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। आज राज्य में हर दिन 14 किलोमीटर सड़क बन रही है, जो देश में सबसे ज्यादा है। शाह दो दिन के लिए असम दौरे पर हैं। उन्होंने कछार के नाथनपुर गांव से 6,900 करोड़ रुपए की 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत देशभर के 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता सीमावर्ती गांवों का विकास है। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम उसी दिशा में उठाया गया कदम है। योजना के दूसरे चरण में 6,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

● बांग्लादेश से सटे ब्लॉकों का समग्र विकास होगा- वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे 334 ब्लॉकों का समग्र विकास किया जाएगा। योजना का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों से पलायन रोकना और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से होने वाली घुसपैठ पर अंकुश लगाना है। पिछले 10 साल में भाजपा ने असम के विकास को नई दिशा दी है। अगले पांच साल में हम असम को बाढ़मुक्त राज्य बनाएंगे। असम पिछले 10 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बना है। शाह नाथनपुर बार्डर भी पहुंचे।

फ्लाइट मैनेजर ने फांसी लगाई, मौत

भोपाल (नप्र)। भोपाल के परवलिया सड़क स्थित शांति एनक्लेव में रहने वाले एक एयरलाइंस कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है। पुलिस ने एफएसएल टीम से मौके का निरीक्षण कराने के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय मुर्तजा हसन, पिता परवेज हसन, निवासी शांति एनक्लेव, परवलिया सड़क थाना क्षेत्र, के रूप में हुई है। वह इंडिगो एयरलाइंस में फ्लाइट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसने पांच साल पहले लव मैरिज की थी और उसकी चार साल की एक बेटी है।

देर रात पत्नी ने देखा शव- जानकारी के अनुसार, गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे मुर्तजा हसन ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसकी पत्नी घर पर ही मौजूद थी। देर रात जब पत्नी की नींद खुली, तो उसने दूसरे कमरे में पति के शव को फांसी के फंदे पर लटका देखा। इसके बाद उसने तुरंत परिजनों को सूचना दी।

गाड़ी के कागज पूरे नहीं तो कटेगा ई-चालान

यूपी में टोल प्लाजा पर शुरू होगी ई-डिटेक्शन प्रणाली

नई दिल्ली (एजेंसी)। अपने वाहन के कागज यानी बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फिटनेस या परमिट में से कोई भी अधूरा रह गया तो आपको अब चालान की मोटी चपत लग सकती है। अधूरे दस्तावेजों के साथ एक्सप्रेस-वे के टोल प्लाजा पर ई-चालान हो सकता है। उत्तराखंड और बिहार में यह तकनीक काम कर रही है और इसे यूपी में भी लागू करने की योजना है। यूपी में एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर इस ईचालान की प्रणाली शुरुआत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेस वे पर शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद प्रदेश के सभी हाईवे के टोल प्लाजा पर भी यह प्रणाली शुरू हो जाएगी। ई-चालान की प्रणाली की बात करें तो 'ई-डिटेक्शन सिस्टम डेटाबेस से जुड़ा होता है।

भोपाल में सफाई कर्मचारियों का फूटा गुस्सा

भोपाल। भोपाल नगर निगम के हजारों सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस (ट्रेड यूनियन 7262) ने आज नगर निगम कमिश्नर को एक कड़ा पत्र सौंपते हुए अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 27 फरवरी 2026 से पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी।

बिहार विधानसभा में यूजीसी के मुद्दे पर जमकर बवाल

● माले विधायक के 'ब्राह्मणवाद' वाली टिप्पणी पर तनातनी

पटना (एजेंसी)। विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष और सत्ता पक्ष ने एक-दूसरे पर खूब टिप्पणी की। मामला उस समय तीखी नोक-झोंक पर पहुंच गया, जब भाकपा (माले) विधायक ने कार्यस्थगन से जुड़ी अपनी सूचना को पढ़ने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 पर रोक को ब्राह्मणवादी कह कड़वी टिप्पणी

कर दी। सत्ता पक्ष के विधायक इस मुद्दे पर खड़े होकर विरोध करने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने यह नियमन दिया कि सदन की कार्यवाही से ब्राह्मण शब्द को हटा दिया जाए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी प्रतिकार करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा उचित नहीं है। संवैधानिक संस्था के निर्णय पर संविधान की शपथ लेने वाले प्रश्न उठा रहे। मैं हर समाज का सम्मान करता हूं। मैं मुजफ्फरपुर में तकनीकी शिक्षा के अध्ययन को गया था। भूमिहार -ब्राह्मण रहते हुए भी मेरी रैगिंग हुई और हॉस्टल से निकाल दिया गया था।

गौरव गोगोई के परिवार को आरोपों में घसीटना गलत

● प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम हिमंता पर साधा निशाना

गुवाहाटी (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा दो दिनों के असम दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से लिंक

होने के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि उनके परिवार और बच्चों को इसमें घसीटना 'गलत राजनीति' है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी के सोनापुर में जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार स्थल जुबीन खेत्रा पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सिंगर जुबीन गर्ग पॉलिटिक्स से ऊपर थे। उन्होंने आगे कहा कि जुबीन गर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी प्यार का संदेश फैलाया। असम कांग्रेस चीफ गौरव गोगोई का पाकिस्तान से लिंक होने के आरोपों पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पॉलिटिक्स में दो तरह के लीडर होते हैं, एक जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं और दूसरे जो पोलराइजेशन करते हैं।

भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन, विरोध

● भड़की बीजेपी ने कहा-देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है। इसी दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में टॉपलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं प्रदर्शनकारियों ने मोदी विरोधी नारे भी लगाए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह बिना शर्ट के प्रदर्शन किया उसे लेकर राजनीति गरमा गई है। बीजेपी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। देश की सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से हंगामा किया ये देश की छवि खराब करने की कोशिश है। कांग्रेस देश का मान सम्मान भूल गई है। बीजेपी नेता ने एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस पर करारा वार किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा,राष्ट्रीय शर्म, ऐसे समय में यह ठीक नहीं है।

● कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए : भंडारी- बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, कांग्रेस पार्टी पर शर्म आती है! राहुल गांधी के निर्देश पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन में हंगामा किया! भारत विरोधी कांग्रेस! कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए! कांग्रेस शहरी नक्सलियों की तरह व्यवहार कर रही है! भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को 'एआई इम्पैक्ट समिट' के एक प्रदर्शनी हॉल में पहुंचकर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए।

शाह मानहानि केस में राहुल गांधी का आरोपों से इनकार

● कहा-राजनीतिक साजिश में फंसाया, सुल्तानपुर में मोची के परिवार से मिले

सुलतानपुर (एजेंसी)। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को यूपी में सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील के मुताबिक, राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है। इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। पेशी के दौरान मौजूद वकीलों के अनुसार, कोर्ट पहुंचने पर राहुल ने जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुनवाई पूरी होने पर धन्यवाद भी कहा। जज ने राहुल से पूछा कि क्या आपको सफाई देनी है। इस पर राहुल ने कहा हां। राहुल करीब 20 मिनट तक

एआई समिट

भारत-अमेरिका का 'पैक्स सिलिका' समझौता

चिप सेक्टर में 10 लाख नौकरियां आएंगी, मोदी-ट्रम्प की मुलाकात जल्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आखिरी दिन भारत और अमेरिका ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर साइन किए हैं। इस समझौते का मकसद दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और एआई की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना और गैर-मित्र देशों पर निर्भरता कम करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिकी आर्थिक मामलों के सचिव जैकब हेलबर्ग ने इस पर साइन किए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अब पैक्स सिलिका का हिस्सा बन गया है, जिससे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने बताया- भारत में पहले से ही 10 प्लांट्स पर काम चल रहा है। बहुत जल्द देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वैष्णव ने यह भी साझा किया कि भारतीय इंजीनियर अब देश में ही एडवांस 2-नैनोमीटर चिप डिजाइन कर रहे हैं।

● मोदी और ट्रम्प की जल्द हो सकती है मुलाकात- सर्जियो गोर ने भारत में हो रही इस समिट को बेहद प्रभावशाली बताया। जब उनसे पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने संकेत देते हुए कहा- बने रहिए। मुझे यकीन है कि सही समय पर यह मुलाकात जरूर होगी। भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ।

मोदी गवर्नमेंट मतलब 'मैक्सिमम ऑप्टिक्स डैमेजिंग इंडिया'

● जयराम रमेश बोले-खुद को विश्वगुरु कहने वाले लोग दुनिया को ज्ञान देने में बिजी हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दिल्ली में आयोजित एआई इम्पेक्ट समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा कहा- मोदी गर्वनेंस का मतलब 'मैक्सिमम ऑप्टिक्स डैमेजिंग इंडिया, यानी भारत को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा रहे है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका-पाकिस्तान बीच रोमांस बिना रुके जारी है। जब ये हो रहा था तब खुद को 'विश्वगुरु' बताने वाले संक्षिप्त शब्दों में दुनिया को ज्ञान दे रहे थे और सीईओ को अपनी एकजुटता दिखाने के लिए मजबूर कर रहे थे। रमेश का कमेंट पीएम मोदी का समिट में आए ग्लोबल टेक लीडर्स के साथ हाथ उठाकर फोटो खिंचाने पर आया है। इधर 19 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी में बोर्ड ऑफ पीस इवेंट में पाकिस्तान के पीएम और

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प की मीटिंग हुई। सम्मिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया के दिग्गज नेताओं और टेक कंपनियों के प्रमुख ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आए। मंच पर पीएम मोदी के साथ सीईओ सैम ऑल्टमैन, एआई एक्सपर्ट्स और अन्य वैश्विक टेक लीडर्स मौजूद थे। ग्रुप फोटो के दौरान सभी नेताओं ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। पीएम मोदी के दोनों ओर खड़े नेताओं ने उनका हाथ थामा, लेकिन सीईओ सैम ऑल्टमैन ने पास खड़े एंथ्रोपिक डारियो अमोदेई का हाथ नहीं पकड़ा। बाद में सैम ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि उस समय क्या करना था। बताया जा रहा है कि पहले भी मतभेद सामने आ चुके हैं। 2021 में कंपनी के भीतर कुछ फैसलों और साझेदारी को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी।

भोपाल मंडल और एडब्ल्यूपीए के बीच एमओयू

56 पूर्व सैनिक बनेंगे पॉइंट्समैन 15 दिन में शुरू होगी तैनाती

भोपाल (नप्र)। पश्चिम मध्य रेलवे का भोपाल मंडल अब पूर्व सैनिकों को रेलवे सेवा से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल करने वाला पहला मंडल बन गया है। मंडल ने स्टेशनों पर पॉइंट्समैन के पदों पर एक्स-सर्विसमैन की तैनाती के लिए Army Welfare Placement Organization (AWPO) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 19 फरवरी को हुए इस समझौते के तहत भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 56 पूर्व सैनिकों को पॉइंट्समैन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। रेलवे प्रशासन के मुताबिक चयनित जवानों की भौतिक तैनाती आगामी 15 दिनों के भीतर शुरू कर दी जाएगी।

दीर्घकालिक सहयोग की ओर कदम

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के मुताबिक यह समझौता दोनों संगठनों के बीच दीर्घकालिक और परिणामदायी सहयोग की दिशा में अहम कदम है। इससे रेलवे और पूर्व सैनिक दोनों को लाभ मिलेगा।

पमरे में पहली पहल

इस समझौते के साथ भोपाल मंडल, West Central Rail2a4 का पहला ऐसा मंडल बन गया है, जिसने पूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए इस तरह का एमओयू किया है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह कदम न सिर्फ पूर्व सैनिकों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि रेल परिचालन और संरक्षा को भी मजबूती देगा।

समझौता ज्ञापन पर मंडल की ओर से वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रोहित मालवीय और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी विजय सिंह ने हस्ताक्षर किए। वहीं एडब्ल्यूपीओ की ओर से सेवानिवृत्त कर्नल मुकेश कुमार तिवारी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सेना से सेवानिवृत्त जवान अनुशासन, जिम्मेदारी और कार्यकुशलता के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति से स्टेशनों पर पॉइंट्स संचालन में दक्षता बढ़ेगी और सुरक्षा मानकों को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

स्कूलों में नए नाम बढ़ाएं, ड्रॉपआउट शून्य करें

कलेक्टरों से सीएस बोले- पंचायत स्तर पर आमदनी के स्रोत करें विकसित

भोपाल (नप्र)। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि पंचायत स्तर पर आय के नए स्त्रोत तलाशें। शिक्षा विभाग की योजनाओं की जिलों में क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव जैन ने नए नामांकन बढ़ाने और ड्राप आउट को जीरो करने पर जोर दिया। जल जीवन मिशन में एकल नल जल योजना की समीक्षा करते हुए रीवा, सिंगरौली, मऊगंज, सीधी, मुरैना और भिंड कलेक्टर्स को कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जैन ने कहा कि कलेक्टर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन तय करें। आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के विकास कार्यों को प्रमुखता दें।

मुख्य सचिव जैन ने मंत्रालय में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं और निर्माण कार्यों को समय अवधि में पूर्ण करें। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योजना बनाकर क्रियान्वयन में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल किया जाना तय करें।

नए नामांकन बढ़ाने और ड्राप आउट को जीरो करने पर जोर- शिक्षा विभाग की योजनाओं की जिलों में क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव जैन ने नए नामांकन बढ़ाने और ड्राप आउट

को जीरो करने पर जोर दिया। उन्होंने शाला के बाहर के चिन्हांकित बच्चों में से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में दर्ज विद्यार्थियों के प्रोफाइल प्रतिशत बढ़ाने पर जबलपुर संभाग और पन्ना एवं बालाघाट जिले की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य प्रदेश में किया जाना है, इसलिए जनगणना कार्य की अवधि को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र संचालित करें ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मुख्य सचिव जैन ने कहा कि बच्चों का एलिमेंट्री प्री स्कूल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है।

यही पढ़ाई उनके आईक्यू में परिलक्षित होती है, इसलिए आगनबाड़ी में 3-6 वर्ष के बच्चों के पंजीयन को बढ़ाये।

गांव में जाकर सैंपलिंग चेकिंग करें, पालकों से वन टू वन चर्चा करें। इसके लिए अपने जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास के अधिकारियों के समन्वय से कार्य कराये।

जिला उत्पादों को दिलाएं जीआई टैग

मुख्य सचिव जैन ने एक जिला-एक उत्पाद योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला के उत्पादों को जीआई टैग दिलवाने के प्रयास करें। उत्पादों की मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने कहा कि कारीगरों के कौशल संवर्धन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आवश्यकतानुसार एक से अधिक उत्पादों को एक जिला-एक उत्पाद में शामिल करने के लिए भी प्रस्ताव भेजे।

मुख्य सचिव जैन ने डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की पहल के अंतर्गत जिलो में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिये। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव जैन ने कहा कि इसमें जितना अधिक कार्य किया जाएगा, प्रदेश के लिए उतना अच्छा होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सभी कलेक्टर अपने जिलों में इस कार्य को प्राथमिकता दें। मुख्य सचिव जैन ने सुशासन, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, संकल्प से समाधान, सीएम हेल्पलाइन का समय सीमा में निराकरण, कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत कृषकों को योजनाओं का लाभ देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिये। बैठक में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव आदि उपस्थित रहें।

पंचायत स्तर पर नए राजस्व स्रोतों को विकसित करने पर जोर

मुख्य सचिव जैन ने ग्रामीण विकास एवं जनजातीय कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में चयनित गांवों को बुनियादी सुविधाओं, गौपालन और डेयरी विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर और आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए 31 मार्च तक विजन डॉक्यूमेंट को पूर्ण करने के निर्देश दिए। समीक्षा में उन्होंने पंचायत स्तर पर नए राजस्व स्रोतों को विकसित करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव जैन ने जल जीवन मिशन में एकल नल जल योजना की समीक्षा करते हुए रीवा, सिंगरौली, मऊगंज, सीधी, मुरैना और भिंड कलेक्टर्स को कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के नवीन स्वीकृत भवनों के लिए निवाड़ी, पांढुर्ना, नीमच, बैतूल, हरदा, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी और भिंड को शीघ्रता से भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव जैन ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र है जो समाज के भविष्य को प्रभावित करते है। प्रदेश और समाज के विकास के लिए इन दोनों क्षेत्र में काम करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य के स्थापना दिवस पर दी बधाई

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य के 39वें स्थापना दिवस पर दोनों राज्यों के प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलकामना करते हुए कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परम्पराओं से समृद्ध अरुणाचल प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त बनाता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित मिजोरम निरंतर विकास, शांति और खुशहाली के नए आयाम स्थापित करता रहे। उल्लेखनीय है कि दोनों ही राज्यों की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले यह दोनों ही अंचल केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे।

प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलों से फसलें गिरीं

उज्जैन, धार समेत 25 जिलों में नुकसान का अनुमान, प्रशासन ने शुरू किया सर्वे

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में 3 दिन से आंधी और बारिश का दौर जारी है। कुछ जिलों में ओले भी गिरे हैं। 24 घंटे के दौरान भोपाल, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, धार, इंदौर, रायसेन, उज्जैन, सागर, छतरपुर समेत 15 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं आंधी की वजह से रतलाम, शाजापुर, उज्जैन में फसलों पर असर पड़ा है। यहां गेहूं की फसलें आड़ी हो गई हैं। इस वजह से दाने पर असर पड़ेगा और किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। 3 दिन में प्रदेश के आधे हिस्से में मौसम बदला हुआ है।

ओलावृष्टि और तेज हवा की वजह से 25 जिलों में फसलों के नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऐसे में सरकार ने भी सर्वे शुरू कर दिया है। राजस्व अमला मैदान में उतरकर प्रभावित फसलों का सर्वे कर रहा है। भोपाल में गुरुवार देर रात से ही हल्की बारिश का दौर जारी है, जो शुक्रवार सुबह तक जारी है। आज धूप भी नहीं निकली है। दूसरी ओर रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बड़े शहरों में तापमान 14 डिग्री से अधिक है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री या इससे अधिक पहुंच गया है।

अगले 2 दिन ऐसा रहेगा मौसम

21 फरवरी- बारिश का अलर्ट नहीं है। दिन में धूप खिली रह सकती है।

22 फरवरी- मौसम साफ रहेगा। कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है।

भोपाल में रातें ठंडी रहती हैं, दिन गर्म

भोपाल में रातें ठंडी रहती हैं, जबकि दिन गर्म। वर्ष 2014 से 2024 के बीच 4 साल दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया था। रात में 7 साल पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। इस बार फरवरी में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार है।

इंदौर में बारिश का ट्रेंड नहीं- फरवरी में इंदौर में बारिश होने का ट्रेंड नहीं है। 2014 और 2015 में बूंदाबांदी जरूर हुई थी। दूसरी ओर दिन में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार ही रहता है।

2019 में तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया था। यहां रात में पारा 10 डिग्री के नीचे रहता है।

ग्वालियर में कड़ाके की ठंड

ग्वालियर में कड़ाके की ठंड का ट्रेंड रहता है। इसकी वजह यहां सीधे उत्तरी हवाएं आना है। 4 फरवरी 2018 की रात में न्यूनतम पारा रिकॉर्ड 1.9 डिग्री दर्ज किया गया था। साल 2019, 2022 और 2023 में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से नीचे ही रहा। पिछले साल ग्वालियर में बारिश भी हुई थी। इस बार यहां फरवरी के पहले ही दिन बारिश का दौर रहा है।

जबलपुर में भी बदला रहता है मौसम- जबलपुर में भी मौसम बदला रहता है। फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहता है, जबकि रात में तापमान न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रहता है।

26.5 टन संदिग्ध गौमांस प्रकरण

खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से सीबीआई जांच की मांग

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 17 दिसंबर 2025 को पुलिस मुख्यालय के सामने 26.5 टन संदिग्ध गौमांस से भरे कंटेनर के पकड़े जाने का मामला अब दिल्ली तक पहुंचाने की तैयारी है। जय मां भवानी हिंदू संगठन के अध्यक्ष भानु हिंदू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने शुक्रवार शाम भवानी चौक पर आंदोलन को अगले चरण में ले जाने का ऐलान किया।

प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में भानु हिंदू ने लिखा है कि 17 दिसंबर को पकड़े गए कंटेनर का मांस नगर निगम से जुड़े ठेका संचालित स्लॉटर हाउस से निकला बताया गया है।

इसे प्रशासनिक लापरवाही और संरक्षण से जुड़ा गंभीर मामला बताया गया है। पत्र में दावा किया गया है कि इतने बड़े स्तर पर संदिग्ध मांस पकड़े जाने के बावजूद अब तक सीमित कार्रवाई ही हुई है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि इस मामले में संगठित नेटवर्क की भूमिका हो सकती है, जिसकी स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच जरूरी है।

1000 पोस्टकार्ड, 1 लाख युवाओं का डिजिटल संकल्प

संगठन ने घोषणा की है कि भोपाल से 1000 पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। साथ ही प्रदेशभर के 1 लाख युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। संगठन का कहना है कि यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास है।

एक साल में तार गिरने से 54 किसानों की मौत

ऊर्जा मंत्री ने कहा- हाईटेंशन लाइन में हर माह होती है पेट्रोलिंग

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में एक साल में बिजली के तार टूटने से 54 किसानों, नागरिकों की मौत हुई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी हाईटेंशन लाइन की मरम्मत के लिए हर माह रूटीन ग्राउंड पेट्रोलिंग एवं वर्ष में दो बार टॉप पेट्रोलिंग कराई जाती है। इसके साथ ही जरूरत होने एवं लाइन में व्यवधान आने पर ट्रिपिंग पेट्रोलिंग कराई जाती है। मंत्री तोमर ने यह जानकारी बीजेपी विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय के सवाल के लिखित जवाब में विधानसभा में दी है। विधायक मालवीय ने ऊर्जा मंत्री से जानकारी मांगी थी कि विद्युत लाइन के खराब तार बदलने की क्या प्रक्रिया है? कितने वर्षों में तार बदले जाते हैं तथा जनवरी 2025 से अब तक प्रदेश में विद्युत लाइन के तार टूटकर चपेट में आने से कितने लोगों या किसानों की मृत्यु हुई है। इस पर मंत्री तोमर ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनियों में विद्युत वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हर साल बारिश के पहले एवं बारिश के बाद दो बार डिटेल सर्वे एवं तकनीकी निरीक्षण कराया जाता है।

42 हेक्टेयर कृषि भूमि से पुजारी का स्वामित्व समाप्त

कोर्ट ने कहा-देवता ही संपत्ति के मालिक, पुजारी सेवक; 200 साल पुराने मंदिर पर सरकार का अधिकार

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर हाईकोर्ट ने अशोकनगर स्थित 200 साल पुराने श्री गणेशजी मंदिर की कृषि भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार घोषित कर दिया है। साल 2006 से लंबित एक महत्वपूर्ण द्वितीय अपील में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निचली अदालतों के आदेश पलटते हुए मंदिर की पूरी जमीन को माफी औकाफ विभाग की संपत्ति माना और पुजारी के निजी स्वामित्व के दावे को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि मंदिर की संपत्ति देवता की होती है और पुजारी केवल उसका सेवक होता है। भूमि रिकॉर्ड में भी यह संपत्ति माफी औकाफ विभाग के नाम दर्ज है। सरकार ने स्पष्ट किया कि पुजारी का कार्य केवल पूजा-अर्चना तक सीमित है। यदि कोई पुजारी मंदिर की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बताता है, तो यह अनुचित है।

सरकार करेगी मंदिर का प्रबंधन और पुजारी की नियुक्ति- न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मंदिर और उससे जुड़ी संपत्ति राज्य सरकार में निहित रहेगी। मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी और पुजारी की नियुक्ति का अधिकार भी सरकार के पास होगा। यह मामला कुल 42 हेक्टेयर कृषि भूमि से संबंधित है, जो तीन गांवों - साडीता (35.003 हेक्टेयर), नागौदखेड़ी (4.922 हेक्टेयर) और मिस्टील (2.790 हेक्टेयर) में स्थित है। पुजारी की ओर से दावा किया गया था कि मंदिर और उसकी जमीन उनके पूर्वजों को लगभग 200 वर्ष पूर्व उत्तराधिकार में मिली थी, इसलिए यह एक निजी मंदिर है। इसी आधार पर निचली अदालतों ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था।

उत्तराधिकार का ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए पुजारी- हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि देवता एक कानूनी इकाई (लीगल पर्सन) हैं और संपत्ति उन्हीं की होती है। पुजारी या प्रबंधक को संपत्ति के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। पुजारी भालचंद राव ने एक पुराना लाइसेंस पेश किया था, जो नई मूर्ति स्थापना से जुड़ा था, लेकिन वे उत्तराधिकार का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर को निजी संपत्ति बताना देवता के हितों के खिलाफ है। उत्तराधिकार और स्वामित्व का प्रमाण न मिलने पर पुजारी का दावा खारिज कर दिया गया।

शाजापुर में टपकती छत के नीचे बोर्ड परीक्षा

शिक्षा विभाग की लापरवाही, 144 छात्रों ने भीगते हुए दिया पेपर

शाजापुर (उज्जैन) (नप्र)। शाजापुर के ग्राम पिपलिया गोपाल स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को कक्षा 5वी और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों को टपकती छत के नीचे बैठना पड़ा। हिंदी का पहला पेपर दे रहे 144 विद्यार्थी टाटपट्टी पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई।

बारिश के कारण परीक्षा कक्ष की छत से पानी टपकने लगा, जिससे बच्चों को भीगते हुए परीक्षा देने को मजबूर होना पड़ा। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक था। तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि बाल्टी और मग रखकर पानी को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद टाटपट्टी और फर्श गीले हो गए थे। बच्चों के कपड़ों पर भी पानी टपक रहा था। यह शासकीय स्कूल तीन दिन पहले भी बच्चों से शौचालय की सफाई कराने के मामले में चर्चा में आया था। अब एक बार फिर शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां छात्रों को ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में परीक्षा देनी पड़ी।

अचानक से आया पानी- इस मामले में स्कूल की शिक्षिका शबाना परवीन ने बताया कि उन्हें बारिश होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होते ही बारिश भी आ गई। अचानक छत के रास्ते क्लास में पानी आना शुरू हो गया।

संपादकीय

लेकिन सुनेगा कौन ?

देश में राज्य सरकारों और कुछ मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा रेवड़ियां बांटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, उसका कोई सकारात्मक असर होगा, इसकी संभावना कम ही है क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए देश, मजबूत अर्थव्यवस्था और विकास से ज्यादा किसी तरह से भी सत्ता पाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आलम यह है कि हर चुनाव के पहले कोई न कोई मुफ्त खोरी की योजना का ऐलान किया जाता है, जिसका एकमात्र मकसद मुफ्तखोरी के बदले में वोट पाकर सत्ता पाना अथवा सत्ता में लौटना है। राज्य की आर्थिकी का भट्ठा बैठ जाए, इसकी किसी को चिंता नहीं होती। मप्र जैसे राज्य कर्ज पर कर्ज लेकर गाड़ी चलाते रहते हैं। राज्य मुफ्तखोरी की जो योजनाएं चला रहे हैं, उनमें केन्द्र सरकार की मुफ्त राशन योजना, फ्री पानी बिजली और नकद बांटना शामिल है। इसी रेवड़ी कल्चर पर तीखी टिप्पणी करते हुए गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। गौरतलब है कि देश में रेवड़ी कल्चर शुरू करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य था, जिसने करीब पैसठ साल पहले स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन की योजना शुरू की थी। बाद में यह राशन और अन्य प्रलोभनों तक आ पहुंची है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधिपति ने सरकारों को नसीहत देते हुए कहा कि आपको लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बनाने चाहिए, ताकि वे कमा सकें और अपनी इज्जत और आत्म सम्मान बनाए रख सकें। जब उन्हें एक ही जगह से सबकुछ मुफ्त मिल जाएगा तो लोग काम क्यों करेंगे। क्या हम ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं? अचानक चुनाव के आस-पास स्कीम क्यों अनाउंस की जाती हैं? अब समय आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, नेता फिर से सोचें। अगर हम इस तरह से उदारता दिखाते रहे तो हम देश के विकास में रुकावट डालेंगे। एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत में कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं? यह समझ में आता है कि कल्याणकारी योजना के तहत आप उन लोगों को राहत दें, जो बिजली का बिल नहीं चुका सकते। जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं और जो नहीं हैं, उनमें कोई फर्क किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टीकरण नहीं है? फिलहाल देश के 19 राज्यों की कुल सब्सिडी का 53% बिजली सब्सिडी पर ही खर्च होता है। 10 राज्यों का अनुमान है कि 2025-26 के राजस्व में घाटा होगा। राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 2024-25 में जीडीपी का 3.3% रहा। 3 साल तक 3% से नीचे था। मार्च 2025 तक राज्यों पर कुल कर्ज जीडीपी का 27.5% था। मार्च 2026 तक 29.2% हो सकता है। राजस्व प्राप्तियां 9.2% की दर से बढ़ीं। अगर मप्र की बात करें तो बजट का 70.87% यानी करीब रू. 2.98 लाख करोड़, मुफ्त योजनाओं, कर्ज की अदायगी-ब्याज, वेतन-भत्तों और पेंशन में जा रहा है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए पैसा ही नहीं बचता।

ग्रेट निकोबार: रणनीतिक विकास या पर्यावरणीय जोखिम

नजरिया

अजय कुमार

लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी बड़ी छलांग की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बड़े कंटेनर जहाज सीधे ग्रेट निकोबार पर रुकने लगते हैं, तो छोटे फीडर जहाजों के जरिए देश के पूर्वी और पश्चिमी तट के बंदरगाहों तक माल पहुंचाना आसान होगा। इससे ट्रांजिट टाइम में कई दिन की बचत हो सकती है और लागत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। रणनीतिक दृष्टि से यह परियोजना भारत की समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती दे सकती है। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार ग्रेट निकोबार का विकास हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी, खुफिया गतिविधियों और त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाएगा।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार आज भारत की रणनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय बहस का केंद्र बन चुका है। करीब 90 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने के बाद यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या भारत विकास और संरक्षण के बीच संतुलन साध पाएगा। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि परियोजना को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति में पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं और इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि हर शर्त का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बड़ा द्वीप है और भौगोलिक दृष्टि से इसकी स्थिति असाधारण मानी जाती है। यह द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य से करीब 35 से 40 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठनों और शिपिंग डेटा के मुताबिक, दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। चीन के कुल ऊर्जा आयात का करीब 60 प्रतिशत और जापान तथा दक्षिण कोरिया के व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। यही वजह है कि इसे हिंद महासागर क्षेत्र की सबसे अहम 'चोक पॉइंट' माना जाता है।

भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक देश के पास इस इलाके में कोई बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का करीब 75 प्रतिशत कंटेनर ट्रांसशिपमेंट विदेशी बंदरगाहों जैसे सिंगापुर, कोलंबो और पोर्ट क्लांग के जरिए होता है। इससे न केवल समय बढ़ता है, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत भी 10 से 15 प्रतिशत तक ज्यादा हो जाती है। रिजर्व बैंक और शिपिंग मंत्रालय से जुड़े अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण भारत की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को गेमचेंजर बताया जा रहा है। यह परियोजना लगभग 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली होगी। इसमें गैलेथिया बे पर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल, ड्यूल यूज सिविल-मिलिट्री एयरपोर्ट, 450 मेगावॉट का गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट और एक नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप शामिल है। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि सिर्फ पोर्ट परियोजना पर करीब 40,040 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पहले चरण में 18,000 करोड़ रुपये की लागत से 2028 तक इसे चालू करने का लक्ष्य है। शुरुआती क्षमता 4 मिलियन टीईयू से अधिक होगी,

जबकि पूरी तरह विकसित होने पर यह क्षमता 16 मिलियन टीईयू तक पहुंच सकती है।

अगर इन आंकड़ों की तुलना की जाए तो भारत का कुल कंटेनर ट्रैफिक 2020 में करीब 17 मिलियन टीईयू था, जबकि चीन का आंकड़ा 245 मिलियन टीईयू से अधिक रहा। यह अंतर साफ दिखाता है कि भारत को अपने समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी बड़ी छलांग की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बड़े कंटेनर जहाज सीधे ग्रेट निकोबार पर रुकने लगते हैं, तो छोटे फीडर जहाजों के जरिए देश के पूर्वी और पश्चिमी तट के बंदरगाहों तक माल पहुंचाना आसान होगा। इससे ट्रांजिट टाइम में कई दिन की बचत हो सकती है और लागत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। रणनीतिक दृष्टि से यह परियोजना भारत की समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती दे सकती है। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार ग्रेट निकोबार का विकास हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी, खुफिया गतिविधियों और त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाएगा। आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता अभियानों के लिहाज से भी यह द्वीप एक अहम बेस बन सकता है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती सामरिक हलचलों के बीच भारत के लिए यह एक अतिरिक्त बढ़त के रूप में देखा जा रहा है।

लेकिन जितनी बड़ी इसकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत है, उतनी ही गहरी इसकी पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं। ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जहां घने वर्षावन, मैंग्रोव, कोरल रीफ और कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। पर्यावरण आकलनों के मुताबिक परियोजना के लिए 8.5 लाख से लेकर 50 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई की आशंका जताई गई है। यह इलाका लेदरबैक समुद्री कछुओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन स्थलों में से एक है। इसके अलावा निकोबार मेगापोड पक्षी, खारे पानी के मगरमच्छ, निकोबार मकाक और रॉबर क्रैब जैसी प्रजातियों पर भी खतरे की बात कही जा रही है यही वजह है कि इस परियोजना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विरोध भी सामने आया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई पर्यावरणविदों ने आरोप लगाया कि परियोजना में पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के भविष्य को नजरअंदाज किया गया है। उनका कहना रहा कि क्लाइमेट चेंज के दौर में समुद्र स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में इतने बड़े तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

ग्रेट निकोबार सिर्फ जैव विविधता का केंद्र नहीं है, बल्कि शोंपेन और निकोबारी जैसी जनजातियों का भी घर है। खासतौर पर शोंपेन जनजाति की आबादी 200 से 300 के बीच बताई जाती है और उन्हें दुनिया की सबसे संवेदनशील आदिवासी जनजातियों में गिना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े पैमाने पर बाहरी आबादी के आने से उनकी पारंपरिक जीवन शैली, संस्कृति और अस्तित्व पर गंभीर असर पड़ सकता है। सरकार का दावा है कि आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और उनके क्षेत्रों में न्यूनतम हस्तक्षेप होगा, लेकिन इस पर लगातार निगरानी की मांग की जा रही है। एनजीटी ने अपने आदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई सख्त निर्देश दिए हैं। इनमें मैंग्रोव पुनर्स्थापन, कोरल ट्रांसलोकेशन, तटरेखा संरक्षण, वन्य जीवों के प्रजनन स्थलों की सुरक्षा और आदिवासी हितों की रक्षा शामिल है। ट्रिब्यूनल ने यह भी साफ किया है कि आईलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नियमों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट भारत के सामने एक बड़ी परीक्षा है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री शक्ति और आर्थिक विकास की जरूरत है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण संतुलन और स्थानीय समुदायों की रक्षा की जिम्मेदारी। आने वाले वर्षों में यह परियोजना किस दिशा में आगे बढ़ती है, यही तय करेगा कि ग्रेट निकोबार भारत के लिए अगला सिंगापुर बनता है या विकास और संरक्षण की टकराहट का सबसे बड़ा उदाहरण। फिलहाल इतना तय है कि यह द्वीप अब सिर्फ भारत का सबसे दक्षिणी भूभाग नहीं, बल्कि देश की समुद्री राजनीति और दीर्घकालिक रणनीति का केंद्र बन चुका है।

'डंकल प्रस्ताव' बनाम 'भारत-अमेरिका अंतरिम संधि 2026' -कुछ सवाल

आर्थिकी

राजीव खंडेलवाल

(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास)

फरवरी 2025 से चल रही भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के परिणामस्वरूप 6 फरवरी को अंतरिम समझौते के 'प्रथम भाग' की घोषणा की गई। औपचारिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर मार्च 2026 तक हस्ताक्षर होने की संभावना है। 6 फरवरी को जारी संयुक्त वक्तव्य के तुरंत बाद, 'व्हाइट हाउस' से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी कार्यकारी आदेश ने इस अंतरिम समझौते की कुछ शर्तों को लेकर कुछ नए प्रश्न व 'भ्रम' की स्थिति अवश्य खड़ी कर दी है। परंतु भारत सरकार 'उदये सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तीमेती च....' सुक्ति का अनुसरण करती हुई पूर्ण रूपेण निस्पृह भूमिका में है। अतः

प्रश्न उठना स्वाभाविक है, हमने क्या पाया-क्या खोया? इससे भी बड़ा प्रश्न–क्या हम एक बार फिर 1991-94 के डंकल दौर जैसी बहस के मुहाने पर खड़े हैं?

संधि के प्रमुख प्रावधान

1. भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकन टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत (कुछ पर तत्काल प्रभाव से)।
2. रूस से तेल आयात में कमी के बदले अतिरिक्त 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ हटाने का संकेत दिया गया है।
3. भारत ने अमेरिकी औद्योगिक एवं कुछ कृषि उत्पादों (जैसे DDGS, सोयाबीन ऑयल, नट्स, फल, वाइन आदि) पर टैरिफ कम अथवा शून्य करने की सहमति दी है।
4. अगले पाँच वर्षों में 500 बिलियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी उत्पाद–ऊर्जा, विमानन, रक्षा व तकनीक–खरीदने की मंशा जताई गई है।
5. मूल देश नियम (rules of origin)।
6. बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)।

7. गैर-शुल्क बाधाएं।

पहली नज़र में यह 'गिव एंड टेक' सौदा प्रतीत होता है। परंतु वास्तव में दूर के ढोल सुहावने समान है।

डंकल प्रस्ताव: 1991-94 का दौर याद कीजिए। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफस एंड ट्रेड (GATT) के महानिदेशक आर्थर डंकल द्वारा प्रस्तुत मसौदा, जिसे प्रचलित भाषा में 'डंकल प्रस्ताव' कहा गया, उरुग्वे दौर (1986-1994) की बहुपक्षीय वार्ताओं का परिणाम था। इसमें कृषि, सेवाएं (GATS), बौद्धिक संपदा (TRIPS), वस्त्र, सब्सिडी और व्यापार नियमों में व्यापक बदलाव शामिल थे।

तुलना बेमानी: डंकन बहुपक्षीय वार्ताओं का मसौदा था, जबकि भारत अमेरिका द्विपक्षीय है। यद्यपी दोनों ने अपने-अपने समय में राष्ट्रीय स्वायत्त, कृषि सुरक्षा और आर्थिक संतुलन पर लगभग एक से ही वैचारिक बहस को जन्म दिया। अतः यहां तुलना विषय वस्तु की नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण और सार्वजनिक प्रतिक्रिया की है।

परिणाम : तत्कालीन भारत सरकार पर जब डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का अंतरराष्ट्रीय दबाव था तब भाजपा और संघ के कई संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर डंकल प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। कहा गया था कि भारत का कृषि क्षेत्र चौपट हो जाएगा और आर्थिक स्वायत्तता गुलामी में बदल जाएगी। परंतु परिणाम क्या हुआ? डब्लूटीओ की सदस्यता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। औसत विकास दर 4-5 प्रतिशत से बढ़कर 7-8 प्रतिशत तक पहुंची। आज भारत विश्व की चौथी इकॉनामी होकर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। अर्थात, उस समय की आशंकाएँ कुछ हद तक निर्मूल सिद्ध हुईं।

स्वस्थ आलोचना क्यों नहीं : हाल में अमेरिका के साथ हुआ समझौता के विरुद्ध 'उड़ि जहाज का पंछी फिरि जहाज पर आये' की तर्ज पर विपक्ष के स्वर उसी तरह से उठ रहे हैं। इतिहास अपने को दोहरा रहा है। लेन-देन के इस युग में कोई भी आर्थिक नीति, समझौते, अनुबंध, पूर्णतः न तो लाभकारी होता है, न हानिकारक। अहस्ताक्षरित अंतरिम द्विपक्षीय व्यापारिक सौदे की घोषणा को भारत ने ऐतिहासिक बताते हुए जिस तरह से स्वागत किया है, उस परिप्रेक्ष्य में उसके एक-एक बिंदु पर विचार करने पर स्थिति कुछ स्पष्ट हो सकती है।

अनुबंध के नुकसान

1. **टैरिफ में कमी : लाभ या भ्रम?** 50 प्रतिशत से 18 प्रतिशत टैरिफ घटना। टैरिफ युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व औसत टैरिफ लगभग 3 प्रतिशत था, तो 18 प्रतिशत अभी भी अधिक है। 'न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी' वाली स्थिति।
2. **भारतीय बाजार का खुलना:** भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ शून्य तक लाने पर घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ेगा। 'विदेशी उत्पाद सस्ते होंगे तो स्थानीय उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं।'
3. **पांच सौ बिलियन डॉलर का व्यापार:** मतलब अगले 5 सालों मे भारी आयात से 'व्यापार संतुलन' अमेरिका के पक्ष में झुक जाएगा। अभी तक व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में था।
4. **ऊर्जा नीति पर प्रभाव:** रूस से सस्ता तेल लेना भारत की व्यावहारिक नीति देश हित में रही है। वैकल्पिक स्रोत अमेरिका या वेनेजुएला महंगे पड़ेंगे। परिवहन (लॉजिस्टिक) सहित लागत बढ़ेगी।
5. **कृषि क्षेत्र की दुविधा:** कृषि मंत्री का यह कथन कि किसानों के सुरक्षित रहेंगे। मतलब गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। यदि सोया तेल या अन्य कृषि उत्पाद सस्ते आयात होंगे, तो घरेलू उत्पादकों पर असर पड़ेगा। क्या भारत दबाव में है? विपक्ष का आरोप है कि यह समझौता अमेरिकी दबाव का परिणाम है। वस्तुस्थिति यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शर्तें परस्पर सहमति से तय होती हैं। यदि भारत ने कुछ शर्तें स्वीकार की हैं तो, वह अन्य लाभों के लिए रणनीतिक संतुलन का हिस्सा हो सकता है।

भारत की संप्रभुता व सार्वभौमिकता पर आघात नहीं– पिछले एक वर्ष से अमेरिका बल्कि ट्रंप भारत के संदर्भ में एक के बाद एक विषयों और नीतियों को लेकर पहल कर घोषणा कर रहा है। उसी कड़ी में इस व्यापारिक घोषणा में तेल खरीदने की संबंध में भारत पर जो शर्त थोपी गई है, उन सब पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी? इन सबको लेकर विपक्षी दल व राजनैतिक टिप्पणीकार उक्त परसेप्शन अवश्य बना रहे है, जो गलत है। वस्तुतः यह संप्रभुता का प्रश्न नहीं, बल्कि नीति गलत होने का मुद्दा अवश्य हो सकता है। संप्रभुता और गरिमा के प्रश्न पर सरकार को स्पष्ट संवाद करना चाहिए।

WTO में चुनौती क्यों नहीं?: जब अमेरिका ने एकतरफा टैरिफ बढ़ाए थे, तो विश्व व्यापार संगठन में औपचारिक चुनौती क्यों नहीं दी गई? यह रणनीतिक चुप्पी थी अथवा कमजोरी, विचारणीय है।

आर्थिक संधियाँ राजनीति की शतरंज नहीं, राष्ट्रहित की दीर्घकालिक रणनीति होती हैं। आज जो शंका है, वही कल अवसर भी बन सकती है। सरकार और विपक्ष–दोनों का दायित्व है कि वे स्वस्थ आलोचना करें, न कि 'आँख मूँद कर समर्थन' या 'आँख दिखाकर विरोध'। राष्ट्रहित दलगत सीमाओं से ऊपर होता है।

पराए मॉल की फजीहत

कटाक्ष

अरुण अर्णव खरे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

'बच्चू, कुछ सुना तुमने?'

'भले चंगे कान हैं तो सुनूँगा ही। सुनने की आदत है इन्हें, रोज़ ही बहुत कुछ सुनता रहता हूँ' - बच्चू ने रूखेपन से उत्तर दिया।

'अरे, मैं रोज़-रोज़ की सुनी-सुनाई बातों की नहीं कह रहा। आज की ताज़ा ख़बर की बात पूछ रहा हूँ।'

'अच्छा ! कौन सी ताज़ा खबर?'

'वही, माल किसी का और नाम अपना'

'इसमें ताज़ापन क्या है? हम तो वर्षों से यह नेक काम करते आ रहे हैं, राम राम जपना, पराया माल अपना। अब तो जो हमें पसंद आता है उसका नाम बदल कर अपने नाम कर लेते हैं'

'बच्चू, तुम बात को समझ नहीं रहे हो'

'समझ रहा हूँ दादा, सब समझ रहा हूँ। दूसरों की चीज़ अपनी बनाने की कला में हम विश्वगुरु हूँ। निर्मल भारत योजना किसकी थी, उसे स्वच्छ भारत मिशन करके अपना बना लिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम को प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना नाम देकर अपना लिया। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्राम ज्योति योजना हो गई। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। हाल में मनरेगा को भी वीबी जीरामजी बना दिया। ऐसे बहुत उदाहरण हैं गिनाने को, शहर किसी ने बसाए पर नाम किसी और के हो गए। यह सब तो हमारे देश में हर दिन होता ही रहता है'।

'अरे तुम बहुत नादान हो, ये सब तो अंदरूनी मसले हैं लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह अंतरराष्ट्रीय है, इसने हमारी अन्तरराष्ट्रीय बेइज़्ज़ती कराई है'।

'यू मीन इंटरनेशनल थूथू'

'हाँ हाँ वही'

'तो हुआ क्या ऐसा'

'उन्होंने मेले में चीनी कुत्ते को अपना बनाकर पेश कर दिया'

'तो तुम क्या चाहते थे, पाकिस्तानी कुत्ते को अपना बताते'

'तुम अक़्ल से पैदल हो बच्चू, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है वैसा कुत्ता पैदा करने की'

'अच्छा ! तब तो सब कुछ साफ़ हो गया। चीनी कुत्ता क्यूट होगा, इसलिए उसे अपना कह दिया होगा।'

'अरे वह क्यूट-व्यूट नहीं, ए.आई. पॉवर्ड कुत्ता है, बेहद ज्ञानवान, खोजी प्रवृत्ति का।'

'ख़ाक खोजी प्रकृति का है, अपने लिए ढंग का मास्टर नहीं खोज पाया, संस्थान की ग्लोबल किरकिरी करा दी। खोजी प्रकृति के कुत्ते की हमें जरूरत ही क्या थी, हमारे यहाँ तो पत्रकार भी अब खोजी नहीं रहे। विज्ञानं में खोज करने की जरूरत हम समझते नहीं, वह तो दुनिया के दूसरे मुल्क कर ही रहे है। हमें जो खोजना होता है हम खोज लेते हैं। आजकल हम हर जगह पर अपनी विरासत खोज रहे हैं। तुमने कहा वह ज्ञानवान है, पर ज्ञान के साथ विवेकशील होना भी जरूरी है। उसमें जरा सा विवेक होता तो खुद ही आगे आकर कह देता कि हमें इनने ही पैदा किया है'।

'बच्चू ऐसे कुत्ते झूठ नहीं बोलते'

'यही तो दिक्कत है। हमें झूठ को सच मानने की लत है। कुत्ते को झूठ बोलना आता नहीं और दुनिया की दिलचस्पी केवल सच में है। अब भद्द पिटना ही थी सो पिट गई।'

'सही कह रहे हो बच्चू ! मेरी सलाह है, चीन को अपना बनाने की भूल न करे कोई।'

झूठ जरूरी हो गया है क्योंकि झूठों का ही बोलबाला है

व्यंग्य

मुकेश नेमा

लेखक मप्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

सबसे पहले तो आप इस बात को नज़रअंदाज़ कीजिए कि गलगोटिया वाली मैडम झूठ बोली। आप ये देखिए उन्होंने कितनी शालीनता और धैर्य रखते हुए ग़लतबयानी की। अपने झूठ की रक्षा के लिए वे कितनी सन्निद्ध थी। ये देखिए उन्हें खुद पर कितना भरोसा है।बोलने वाले को भी खुद पर भरोसा हो ,वो विनम्र हो तो झूठ असरकारी हो जाता है। असरकारी की सराहना करना कायदे की बात है। सच्ची बात यह कि वो पहली और अकेली नही इस दुनिया मे जो झूठ बोलता हो। और फिर सुंदर महिलाओं को झूठी कहना अशिष्टता होती है ऐसे मे मैं भारतीयों को इन मैडम की लानत मानत करते देख चकित हूँ, और उनकी तरफ़दारी करना अपना फर्ज मानता हूँ।

पुराने जमाने के लोग मानते थे कि सच बोलने पर जान ,माशूक़ा,बीबी या कुर्सी जाने का खतरा हो तो झूठ बोलना शास्त्र सम्मत है।झूठ बोलने को हमारे यहां बुरा नही माना जाता। मैडम अनुभवी है। उन्होंने झूठ बोलने की कला को परिष्कृत ही किया है। वो निर्दोष भाव से झूठ बोली। बस इसलिए बोली क्योंकि उन्हें ऐसा करना पसंद था। वो बिना फ़ायदे नुकसान के झूठ बोली, इसलिए उनकी सराहना की जाना चाहिए। इस झंझावाती और झंझटी दुनिया मे अपने पैर मजबूती से जमाए रखने के लिए झूठ बोलना जरूरी है। ऐसे मे मैडम ने वो ही किया जो करना चाहिए और पूरी दीदादिलेरी से किया इसलिए मैं उन्हें तारीफ ए काबिल मानता हूँ।

मैडम अपने काम में शानदार हैं।उन्होंने और झूठ बोला और उस पर अड़ी रही। उसे बार बार दोहराकर कर उसमें जान फूँकने की कोशिश की। उन्होंने अपने झूठ के खिलाफ़ पेश किये गये तमाम तर्कों को बिना सुने ख़ारिज किया। अपने झूठ को सहारा देने के लिये उप झूठ,गवाह और सबूत भी गढ़ कर रखे। वे हारी पर उन्होंने पोरस की तरह बर्ताव किया। विजेता की आँखों में आँखें डालकर बात करती रहीं वो इसलिए वो ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार की हकदार है।

उन्होंने अपने झूठ को पाँव दिए। वो इस कदर आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि सामने वालो का कॉन्फ़िडेंस डगमगा गया। वो हारी पर जीती जैसी लगी। उन्होंने सच और झूठ के बीच के मामूली फर्क को मिटा दिया। वो झूठ बोली,पर इसलिए बोली क्योंकि झूठ हमेशा फ़ायदे के लिये बोला जाता है जबकि सच की तासीर नुक़सान करवाने की होती है। इसलिए बोलीं क्योंकि झूठ बोलना नैसर्गिक मनोवृत्ति होती है इंसान की जबकि सच बोलने के लिये मन को समझाना पड़ता है।वो झूठ इसलिए बोलीं क्योंकि झूठ हमेशा खुशी और राहत का पैग़ाम लेकर आता है जबकि सच बोलने पर आपको मातम का सामना करना पड़ सकता है।

वो कमाल है। वो झूठ बोली, सामने वाले से सच बोलने की उम्मीद की और साथ में उसे गधा और बेवकूफ भी समझा। झूठ बोलने का यही सबसे सही तरीका है। झूठ इसलिए भी बोली वो क्योंकि झूठ के चाहने वाले ज़्यादा है दुनिया में,और वो सच की बनिस्बत जल्दी असर करता है। इसे ऐसा समझें झूठ एलोपैथी है और सच होम्योपैथी की तरह है।सच दाल दलिया जैसी बेस्वाद चीज है जबकि झूठ चिकन करी जैसी शाही डिश है। झूठ बोलने से जिंदगी मे जायका बना रहता है और मैडम ने हमें एक बेहतरीन कुक होकर दिखाया है।

झूठ बोलने से परहेज करना ठीक नही। यदि ज़रूरी होने पर भी झूठ बोलने में संकोच या लिहाज़ करेंगे आप तो मारे जायेंगे। आजकल झूठ इसलिये भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि बोलबाला झूठो का ही है। मैडम प्रोफेसर है, उनसे सीखना चाहिए आपको। वैसे झूठ बोलने में अच्छा हूँ मैं,पर और बेहतर होना चाहता हूँ। सो अब अता पता ढूँढा जाएगा इन प्रोफ़ेसर साहिबा का ताकि उसने ट्यूशन ली जाकर बचा हुआ जीवन सफल किया जा सके।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

डॉ. अशोक कुमार भार्गव

(पूर्व आईएएस, मोटिवेशनल स्पीकर)

मातृभाषा हमारी आत्मा की आवाज

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में लिखने-पढ़ने, सीखने समझने संवाद स्थापित करने का अधिकार है क्योंकि मातृभाषा हमारी आत्मा की आवाज होती है। वह मात्र शब्दों का समूह या जाल नहीं होती वरन हमारी संस्कृति, संस्कार, मूल्य, परंपरा, विरासत और अस्मिता की पहचान होती है। वह हमारी सोच,समझ, भाव, विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, सामाजिक गठन, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन में सहायक होती है।

सामान्य अर्थों में बच्चा जन्म लेने के बाद पहली बार जिस ध्वनि स्पर्श या संकेत में मां शब्द कहता है वही उसकी मातृभाषा होती है जो वह मां के झूले पालने में, मां की पवित्र गोद में धीरे-धीरे सीखता है। यह उसके भावनात्मक लगाव, सामाजिक जुड़ाव,जटिल मानसिक परिस्थितियों को समझने, संज्ञानात्मक विकास और रचनात्मकता का आधार बनती है। 21 फरवरी को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पृष्ठभूमि सन 1952 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश में हुए भाषाई आंदोलन से संबंधित है। सन् 1947 में पाकिस्तान के जन्म के बाद उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया और पूर्वी पाकिस्तान में भी उर्दू को ही राष्ट्रभाषा के रूप में थौपने का प्रयास किया किंतु पूर्वी पाकिस्तान ने अपनी मातृभाषा बांग्ला को आधिकारिक भाषा घोषित करने की मांग की जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया फल स्वरुप 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया जिसे पाकिस्तान की पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए बर्बरता पूर्वक समाप्त कर दिया जिसमें अनेक छात्र मारे गए।

बांग्लादेश में यह दिवस दुखद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मातृभाषा के इस भाषाई संघर्ष को मान्यता देने के लिए वैश्विक स्तर पर मातृभाषा दिवस मनाने की मांग कनाडा के बंगाली नागरिक रफीकुल इस्लाम ने की थी जिसे यूनेस्को ने स्वीकार कर किया और 21 फरवरी 2000 को पहला विश्व मातृ भाषा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, बहुभाषिकता के प्रति चेतना, लुप्त प्राय भाषाओं को संरक्षित करना और मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। वास्तव में यह दिवस अपनी मातृभाषा के प्रति निष्ठा, वचनबद्धता, ममत्व, लगाव और भावनात्मक जुड़ाव के प्रकटिकरण का स्मारक दिवस है। यूनेस्को का अनुमान है कि दुनिया में बोली जाने वाली 7000 भाषाओं में से 40 प्रतिशत भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया में मात्र 100 से भी कम भाषाओं का उपयोग हो रहा है। अन्य भाषाएं इस दौर की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ नहीं हो पा रही हैं।

यह मानवीय सभ्यता के लिए एक गंभीर संकट है। वैश्वीकरण,शिक्षा और मीडिया में प्रमुख भाषाओं के प्रभुत्व, औपनिवेशिक विरासत, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं तथा आर्थिक कारणों से समुदायों के विस्थापन, क्षेत्रीय तथा अल्पसंख्यक भाषाओं पर तथाकथित पिछड़ेपन या अशिक्षित होने के सांस्कृतिक लांक्षन तथा लिखित में भाषाओं की स्वयं की लिपि न होने के के कारण भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। इनके साथ ही संपूर्ण बौद्धिक सांस्कृतिक विरासत, हमारी पहचान, प्रकृति, गणित, दर्शन, लोकगीत, लोक कथाऐं, कहावतें मुहावरे, कविताएं, गीत, दादी, नानी की कहानियां, अभिव्यक्ति की अनूठी तकनीक आदि सभी भी विलुप्त हो रही हैं। इसलिए भाषाई विविधता और लुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण, उनके पुनरुद्धार की आवश्यकता, मातृ भाषाओं का सम्मान और मातृभाषा में बोलने के मूल अधिकार की रक्षा करना आज सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है। इसी वास्तविकता को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 2022 - 2032 को अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी भाषा दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दशक इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम विलुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर सकारात्मक पहलों को अंजाम दें क्योंकि भाषाई विविधता हमारी ताकत है विरासत है।

मातृभाषा की महत्ता अनुपम होती है।मातृभाषा के बिना व्यक्ति गूंगा हो जाता है। प्रखर पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था कि मुझे देश की आजादी और भाषा की आजादी इनमें से किसी एक को चुनना हो तो मैं निःसंकोच भाषा की आजादी चुनूंगा। क्योंकि, देश की आजादी के बावजूद भाषा की गुलामी रह सकती है। अगर भाषा आजाद हुई तो देश गुलाम नहीं रह सकता। वास्तव में भाषा का रिश्ता महज संवाद तक सीमित नहीं होता यह व्यक्ति की अस्मिता और स्वाभिमान से भी जुड़ी होती है। औपनिवेशिक शासन के घोर विरोधी और स्वभाषा के समर्थक केन्या के महान लेखक थ्योंगो ने कहा था कि जब मैं उनकी भाषा में लिखता था तो उन सब का प्रिय लेखक था लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मातृभाषा गिकुयू में लिखना प्रारंभ किया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तब मेरी समझ में आया कि आजादी तक सिर्फ अपनी मातृभाषा के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। महात्मा गांधी ने भी 1937 में वर्धा में नई तालीम के प्रस्ताव में बच्चों को अनिवार्य निशुल्क शिक्षा के साथ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने और कौशल उन्नयन पर बल दिया था।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यदि से मैंने मातृभाषा में विज्ञान और गणित की शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो मैं आज इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बन सकता था। अगर विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाना है तो विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे जल्दी सीखते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। निसंदेह मातृभाषा हमारी संस्कृति और सामाजिक पहचान से जुड़ी होती है। मातृभाषा से ही हमारी परंपराएं, रीति रिवाज और बौद्धिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। अतः मातृभाषा के बिना हम अपने भावों,विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होते।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के अमृत काल में भी हम गुलामी के प्रतीक चिन्हों से चिपके हुए हैं। विकसित भारत के स्वप्न की पूर्णता हमारी एकजुट एकता, राष्ट्र के प्रति नागरिक कर्तव्यों का पालन, विरासत पर गर्व और गुलामी की हर सोच से मुक्ति पर निर्भर करती है। गुलामी की जंजीरें टूट गई किंतु अंग्रेजी का प्रभुत्व आज भी कायम है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश दिलाना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। जबकि मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त करना बच्चों की बौद्धिक रचनात्मकता और संज्ञानात्मक विकास के लिए अहम होती है। मातृभाषा का सम्मान और संरक्षण करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हम अपनी भाषाओं से दूर होते जा रहे हैं। यदि हमारी भाषा अस्तित्वहीन हो गई तो हमारी संस्कृति परंपरा और विरासत भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए मातृभाषा का सम्मान, संरक्षण और संवर्धन बहुत आवश्यक है। मातृभाषा के बिना हमारा जीवन अर्थहीन है। जब भाषा मजबूत होती है तो देश भी मजबूत होता है और जब भाषा गुलाम होती है तो देश भी गुलाम हो जाता है। इसलिए हमें अपनी मातृ भाषा में अभिव्यक्ति पर गर्व होना चाहिए।

मातृभाषा से प्रेम राष्ट्र से प्रेम होता है। मातृभाषा की उपेक्षा राष्ट्रीय स्वाभिमान की उपेक्षा होती है। हमें अन्य भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए आवश्यकतानुसार उन्हें सीखना भी चाहिए किंतु मातृ भाषा की बलि देकर नही। हमें हर संभव परिस्थितियों में मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह हमारे सम्मान का प्रतीक है।सोशल मीडिया के सभी पटलों पर मातृभाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस देश के नागरिकों में अपनी मातृभाषा के प्रति आत्माभिमान का भाव नहीं होता उनका विश्व में भी कहीं सम्मान नहीं होता। भाषा बचती है तो संस्कृति बचती है। इस दिवस की सार्थकता यह संकल्प लेने में है कि बहु भाषावाद को प्रोत्साहित करते हुए भाषाई विविधता का सम्मान करें। विश्व की अन्य भाषाओं के प्रति अनुराग का भाव रखें। नई प्रौद्योगिकी में अपनी भाषा का उपयोग करें। भाषा को भूलें नहीं उसकी जड़ों से जुड़े और आत्मसात करें।

पर्यावरण

जयदेव राठी

लेखक एडवोकेट हैं।

एआई की कीमत : पानी, ऊर्जा और पर्यावरण का संकट

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज की दुनिया में एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रही है। स्वचालित संवाद प्रणालियों से लेकर बहुभाषी सहायकों तक, ये डिजिटल उपकरण हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इस तकनीकी क्रांति की एक छिपी हुई कीमत है- विशाल पैमाने पर पानी और ऊर्जा की खपत, जो पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर रही है। जब लाखों लोग प्रतिदिन इन स्वचालित प्रणालियों का उपयोग करते हैं, तो इसके पर्यावरणीय प्रभाव उतने ही सूक्ष्म हैं जितने खतरनाक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती मांग ने आंकड़ा भंडारण केंद्रों की संख्या और आकार में अभूतपूर्व वृद्धि की है। वर्तमान में विश्वभर में लगभग 11,000 ऐसे केंद्र संचालित हैं और इनकी जल खपत चौंकाने वाली है। एक मध्यम आकार का आंकड़ा भंडारण केंद्र प्रतिदिन लगभग 3 लाख गैलन पानी की खपत करता है, जो करीब 1,000 परिवारों की वार्षिक आवश्यकता के बराबर है। लेकिन जब बात बड़े केंद्रों की आती है, तो यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला हो जाता है - प्रतिदिन 50 लाख गैलन तक, जो 10,000 से 50,000 लोगों के एक छोटे शहर की जरूरत के बराबर है।

अमेरिका में 2024 में इन आंकड़ा भंडारण केंद्रों ने प्रतिदिन लगभग 44.9 करोड़ गैलन पानी का उपयोग किया, जो सालाना 163.7 अरब गैलन के बराबर है। टेक्सास राज्य में स्थिति और भी चिंताजनक है। ह्यूस्टन उन्नत शोध केंद्र और ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, टेक्सास में ये केंद्र 2025 में 49 अरब गैलन पानी का उपयोग करेंगे, और यह आंकड़ा 2030 तक बढ़कर 399 अरब गैलन तक पहुंच सकता है। कैलिफोर्निया के रिवरसाइड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रत्येक 100 शब्दों की स्वचालित संगणना क्वेरी लगभग 519 मिलीलीटर पानी का उपयोग करती है - एक बोतल के बराबर। यह मात्रा भले ही मामूली लगे, लेकिन जब दुनियाभर में अरबों लोग प्रतिमिनट इन प्रणालियों को अनुरोध भेजते हैं, तो यह एक विशाल जल संकट का रूप ले लेती है। एम्स्टर्डम के मुक्त विश्वविद्यालय के एक हालिया शोध के अनुसार, 2025 में केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों का जल पदचिह्न 312.5 से 764.6 अरब लीटर तक पहुंच सकता है – यह विश्वभर में बोतलबंद पानी की वार्षिक खपत के बराबर है।

पानी की खपत के साथ-साथ, इन आंकड़ा भंडारण केंद्रों की ऊर्जा खपत भी चिंता का विषय है। एक पारंपरिक केंद्र 10,000 से 25,000 घरों जितनी बिजली का उपयोग करता है। लेकिन नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-केंद्रित विशालकाय भंडारण केंद्र एक लाख या उससे अधिक घरों जितनी बिजली खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रमुख तकनीकी कंपनी का लुइसियाना में प्रस्तावित महाकाय आंकड़ा केंद्र पूरे न्यू ऑरलियन्स शहर से दोगुनी बिजली खपत करेगा, जबकि व्योमिंग में योजनाबद्ध एक अन्य केंद्र पूरे राज्य के सभी घरों से अधिक बिजली का उपयोग करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण के अनुसार, 2024 में इन केंद्रों ने विश्वभर में लगभग 415 टेरावाट-घंटे बिजली की खपत की, जो वैश्विक बिजली खपत का लगभग 1.5 प्रतिशत है। यह थाईलैंड जैसे देश की वार्षिक ऊर्जा खपत के बराबर है। अनुमान है कि यह आंकड़ा 2030 तक बढ़कर 945 टेरावाट-घंटे हो जाएगा – जो जापान की वर्तमान बिजली मांग के बराबर है। अमेरिका में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी समीक्षा के विश्लेषण के अनुसार, 2024 में अमेरिकी आंकड़ा भंडारण केंद्रों ने लगभग 200 टेरावाट-घंटे बिजली का उपयोग किया। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2028 तक केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता-विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बिजली की खपत 165 से 326 टेरावाट-घंटे प्रति वर्ष तक बढ़ जाएगी, जो अमेरिका के 22 प्रतिशत घरों को सालाना बिजली देने के बराबर है। ऊर्जा खपत का सीधा परिणाम कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि है। वर्तमान में ये केंद्र बिजली की खपत से लगभग 18 करोड़ टन कार्बन द्विऑक्साइड का अप्रत्यक्ष उत्सर्जन करते हैं। एम्स्टर्डम के मुक्त विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार, 2025 में केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों का कार्बन पदचिह्न 3.26 से 7.97 करोड़ टन कार्बन द्विऑक्साइड उत्सर्जन के बीच हो सकता है - जो न्यूयॉर्क शहर के कार्बन पदचिह्न के बराबर है। 2024 में अमेरिका में उपयोग की जाने वाली बिजली की कार्बन सघनता अमेरिकी औसत से 48 प्रतिशत अधिक थी। इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका में 60 प्रतिशत बिजली अभी भी जीवाश्म ईंधन - कोयला और प्राकृतिक गैस से आती है। एक प्रमुख खोज इंजन कंपनी के कार्बन उत्सर्जन में पिछले पांच वर्षों में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि एक अन्य सॉफ्टवेयर दिग्गज में 2020 से 23.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। दोनों कंपनियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड अभिकलन को इस वृद्धि का मुख्य कारण बताया है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि एक बड़े भाषा मॉडल को प्रशिक्षित करने में लगभग 500 मीट्रिक टन कार्बन द्विऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ- यह न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक 438 बार कार चलाने के बराबर है। इन वैश्विक आंकड़ों के पीछे स्थानीय समुदायों की वास्तविक कहानियां छिपी हैं। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के न्यूटन जिले में एक सामाजिक मंच कंपनी का आंकड़ा केंद्र प्रतिदिन 5 लाख गैलन पानी खपत करता है - जो पूरे जिले की जल खपत का 10 प्रतिशत है। ओरेगन राज्य के द डेल्स नगर में एक खोज इंजन कंपनी के केंद्रों ने 2021 में शहर की कुल जल खपत का 29 प्रतिशत उपयोग किया, जबकि यह क्षेत्र पहले से ही सूखे की मार झेल रहा है।

समस्या को और जटिल बनाने वाली बात यह है कि अधिकांश तकनीकी कंपनियां अपने पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं करतीं। 2016 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि एक-तिहाई से भी कम आंकड़ा भंडारण केंद्र संचालक जल खपत को दर्ज करते हैं। कंपनियां अक्सर 'कार्बन तटस्थता' का दावा करती हैं- स्वच्छ ऊर्जा प्रमाणपत्र खरीदकर- जबकि उनके वास्तविक स्थानीय उत्सर्जन अप्रकाशित रहते हैं। शोध से पता चलता है कि उनका वास्तविक कार्बन पदचिह्न रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से 662 प्रतिशत तक अधिक हो सकता है। इस गंभीर स्थिति के बावजूद, कुछ आशाजनक समाधान उभर रहे हैं। द्रव-निमज्जन शीतलन और बंद-परिपथ शीतलन प्रणालियां पानी की खपत को 70 प्रतिशत तक कम कर सकती हैं। एक प्रमुख तकनीकी कंपनी ने पिछले वर्ष में प्रति अनुरोध ऊर्जा उपयोग में 33 गुना और कार्बन पदचिह्न में 44 गुना कमी की है। 2024 में अमेरिकी सांसदों ने एक 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर्यावरणीय प्रभाव अधिनियम' प्रस्तुत किया, जो राष्ट्रीय मानक संस्थान को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पर्यावरणीय प्रभाव के मानक विकसित करने का आदेश देता है। कुछ नगर प्रशासनों ने भी सख्त नियम स्थापित किए हैं और इन केंद्रों की निरंतर निगरानी अनिवार्य की है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता निस्संदेह भविष्य की तकनीक है, लेकिन इसे टिकाऊ तरीके से विकसित करना आवश्यक है। एक प्रतिष्ठित पर्यावरण शोध पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन चेतावनी देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्वर उद्योग 2030 तक अपने शून्य-कार्बन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, जब तक कार्बन प्रति संतुलन और जल पुनर्स्थापना तंत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। यह समय की मांग है कि तकनीकी कंपनियां, सरकारें, और समुदाय मिलकर एक ऐसा रास्ता खोजें, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति पर्यावरण की कीमत पर न हो। पारदर्शिता, जवाबदेही, और तकनीकी नवाचार के माध्यम से हम इस तकनीक की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जबकि हमारे ग्रह को भी संरक्षित रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण के अनुसार, यदि सही नीतियां और प्रौद्योगिकियां अपनाई जाएं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग 2035 तक 1,400 मिलियन टन कार्बन द्विऑक्साइड उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं – जो आंकड़ा भंडारण केंद्रों के उत्सर्जन से तीन गुना अधिक होगी। लेकिन इसके लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या हम इस तकनीक का विकास करेंगे, बल्कि यह है कि हम इसे कैसे विकसित करेंगे- और क्या हम इसे इस तरह करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य ग्रह छोड़ सकें। क्योंकि अंततः, एक स्वस्थ पर्यावरण के बिना, कोई भी तकनीकी प्रगति निरर्थक है।

मानसिक सेहत

स्मिता कुमारी

लेखक सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र भोपाल की निदेशक एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक हैं।

प्रेम या उत्पीड़न: इंदौर घटना से सबक लेने की जरूरत

लड़की काउंसलिंग के दौरान बता रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर इतना शक करता था कि एक बार कॉल ना उठाने पर उसके इंटरव्यू स्थल पर पहुंच गया और उसकी दोस्त के सामने उसके हाथ से पेपर छीनकर उसके मुंह पर दे मारा। बाद में मांफी मांगकर कहने लगा उससे बहुत प्यार करता है इसलिए गुस्सा में ऐसा किया। इसमें गिल्ट फीलिंग की जगह लड़की को ही ब्लेम किया कि उसे कॉल उठाकर गुस्सा नहीं दिलाती तो ऐसा होता ही नहीं। ऐसी कई घटनायें समाज में रोजाना आसपास घरों में देखने को मिलती है जिसमें पुरुष गुस्सा, मारपीट को अपने पार्टनर से प्रेम के पर्यायवाची रूप में जताते हैं। उन्हें इस बात की जरा भी अफसोस नहीं होता कि उनका यह व्यवहार मजाक या प्रेम नहीं बल्कि अपराध है जिसे कई लड़कियां या महिलाएं सिर्फ मजबूरी या सामाजिक अवहेलना या आर्थिक रूप से निर्भरता के कारण झेलती हैं।

पिछले दिनों इंदौर में एक बेहद ही दर्दनाक घटना घटी, एक एमबीए की छात्रा को उसके बॉयफ्रेंड ने मर्डर करके उसकी लाश के साथ भी रेप किया। ना तो उसे इस हत्या का अफसोस है, ना ही उसके चेहरे पर कोई अपराधबोध का भाव। हालांकि अभी आरोपी पीयूष के मानसिक जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई है इसलिए इस पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं है कि उसे कौन सी मानसिक बीमारी है या क्यों हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश रेप के मामले में देश में चौथे नंबर पर है और बाल अपराध में पहले नंबर पर। रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया गया है कि 99त्न रेप के मामले में अपराधी परिचित होते हैं। इस पर देखा जाए तो आये दिन महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा चिंता का विषय बनते जा रहा है. एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का सपना देखा जा रहा है तो वही दूसरी तरफ ऐसी अपराधिक घटनाएं बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण में रुकावट बनती जा रही है।

कुछ समय पहले एक लड़की काउंसलिंग के दौरान बता रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर इतना शक करता था कि एक बार कॉल ना उठाने पर उसके इंटरव्यू स्थल पर पहुंच गया और उसकी दोस्त के सामने उसके हाथ से पेपर छीनकर उसके मुंह पर दे मारा। बाद में मांफी मांगकर कहने लगा उससे बहुत प्यार करता है इसलिए गुस्सा में ऐसा किया। इसमें गिल्ट फीलिंग की जगह लड़की को ही ब्लेम किया कि उसे कॉल उठाकर गुस्सा नहीं दिलाती तो ऐसा होता ही नहीं। ऐसी कई घटनायें समाज में रोजाना आसपास घरों में देखने को मिलती है जिसमें पुरुष गुस्सा, मारपीट को अपने पार्टनर से प्रेम के पर्यायवाची रूप में जताते हैं। उन्हें इस बात की जरा भी अफसोस नहीं होता कि उनका यह व्यवहार मजाक या प्रेम नहीं बल्कि अपराध है जिसे कई लड़कियां या महिलाएं सिर्फ मजबूरी या सामाजिक अवहेलना या आर्थिक रूप से निर्भरता के कारण झेलती हैं।

इंदौर की इस घटना में अपराधी हत्या के बाद भी सेक्स पावर की दवा लेकर लड़की के शव के साथ रेप किया, नशा किया और तंत्र-मंत्र का उपयोग कर लड़की की आत्मा से बात करने की कोशिश की। इंदौर की इस दर्दनाक घटना या ऐसी घटनाओं में मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझना जरूरी है -

1. पहली बात यह सामान्य व्यक्ति का व्यवहार बिलकुल नहीं है, ऐसे व्यक्ति एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेक्सुअल सैडिज्म, नेक्रोफीलिया से ग्रसित हो सकते हैं। इसने तंत्र-मंत्र का उपयोग कर लड़की की आत्मा से बातचीत करने की कोशिश की जिससे 'ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ' यानी अवास्तविक रूप से खुद को बहुत श्रेष्ठ समझने का भाव दिखता है। इस व्यक्तित्व वाले इंसान में यह प्रवृत्ति एक दिन में नहीं आती। यह पहले भी कुछ न कुछ हिंसक, असामाजिक व्यवहार दिखाते ही हैं जिसे अकसर परिवार वाले, दोस्त या परिचित इग्नोर कर देते हैं। यह बचपन के ट्रामा, जेनेटिक कारणों, पालन-पोषण, आसपास के माहौल आदि कारणों से हो सकता है, जिसकी जाँच मेडिकल परीक्षण करके विस्तृत केस हिस्ट्री और मनोवैज्ञानिक जाँच से ही पता किया जा सकता है। एंटीसोशल पर्सनालिटी, नेक्रोफीलिया, सेक्सुअल सैडिज्म का लिंगानुपात में रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया है कि यह तीनों समस्याएँ महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कई गुणा ज्यादा है।

2. दूसरी बात लड़कियों को समझना जरूरी है कि कोई आपसे प्रेम करता है तो वह आपको हर्ट नहीं कर सकता। शक करना, पाबंदी करना, चिल्लाना, अपमान करना प्रेम की निशानी नहीं बल्कि अपराध की निशानी है। कोई प्रेम करता है इसलिए आपका अपमान करना उसका हक नहीं हो जाता। ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति से सतर्क रहें। लड़की के मां-पिता भाई-बहन आपस में दोस्त बने, लव मैरिज गुनाह नहीं है। बल्कि प्यार करने वाली बहन-बेटियों से रिश्ता तोड़, उसे डराना, उसे अपराधबोध महसूस कराना भले ही आपके लिए सामाजिक अपराध नहीं हो, लेकिन यह मानवीय अपराध है। दोस्त बनने से कई ऐसी घटनाओं की शिकार हो रही बहन-बेटियां अपने साथ हो रही अपराधिक घटनाओं को आपसे खुलकर बता पाएंगी। परिवार का प्रेम हर कंडीशन में अपने बच्चों के साथ खड़ा होने से होता है ना कि मुंह मोड़ लेने से। अकसर देखा जाता है कि लड़कियों का लड़कों से दोस्ती पर पाबंदी लगा दी जाती है, प्रेम सम्बन्ध में रिश्ते तोड़ लिया जाता है। जरा सोचिए अगर एक बच्चा जिद् में कहीं से गिर जाए तो आप क्या करते हैं? उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं या उसे समझा कर दवा लगाते हैं? अगर आपको एहसास है कि आपके बच्चे ने अपने लिए गलत जीवनसाथी का चुनाव किया है तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि उसके और साथ मजबूती से खड़े रहें ताकि जिद् में वह किसी अपराध की शिकार ना हो। आपके साथ होने से अपराध की घटनाएँ कम हो सकती है।

3. तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इस तरह की घटनाओं को समझने की जिम्मेदारी केवल लड़की या उसके परिवार की नहीं होती, बल्कि लड़के और उसके परिवार को भी है। आप अपने बच्चों के जिद्पना, गुस्सा, हिंसक और असामान्य व्यवहार को अनदेखा ना करें। पुत्र के मोह में हर डिमांड पूरा करके उसे ऐसा ना बनाएं कि वह किसी चीज को ना पाने, या लड़की के इंकार को अपने अहंकार पर लेकर अपराध कर बैठे। उन्हें अपराध की ओर जाने से रोकना है तो उनके असामाजिक व्यवहार को समझें, समय रहते विशेषज्ञओं से सम्पर्क करें और अपने बच्चों को अपराध की ओर बढ़ने से रोकें। अक्सर लोग मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञओं से इस बात पर चर्चा करने से बचते हैं कि उनका बच्चा पागल थोड़े ही है, वह तो जिद्दी है थोड़ा, समय के साथ समझदार हो जायेगा। लड़कों का गुस्सा, जिद्पना, असामाजिक व्यवहार उनको बचपना लगता है और मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञओं से मिलना शर्मिंदगी। फिर जब बच्चे अपराध कर बैठते हैं तो कई लोग उनसे रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं। यह आपको तय करना है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलने में शर्मिंदगी होगी या एक अपराधी के परिवार के रूप में खुद को देखने में। बेशक रिश्ता तोड़ना आसान है और व्यवहार में सुधार कराना मुश्किल। मगर यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि समय रहते बच्चों का दोस्त बनना है, उनके असामान्य व्यवहार में सुधार लाने पर कार्य करना है या रिश्ते से मुँह मोड़ना है।

कैलाश विजयवर्गीय, राजेन्द्र शुक्ल, विजयशाह के पुतलों का दहन किया कांग्रेस ने,की अशोभनीय टिप्पणी

सोहागपुर । ब्लाक कांग्रेस कमेटी एवं नगर कांग्रेस के तत्वावधान में आज मुख्य बाजार में प्रदेश के तीन मंत्रियों कैलाश विजयवर्गीय उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल एवं विजय शाह के पुतलों का दहन किया गया। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ अमूमन पुतला दहन के दौरान पुलिस पुतला छीनने की कोशिश करती है।या चले पुतले पर पानी डालकर बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह आश्चर्यजनक है। उक्त पुतला दहन नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा विधानसभा सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार पर की गई। टिपण्णी के विरोध में किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने श्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ प्रदेश में चरमरा रही स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा कर्नल सोफिया कुरेशी मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना के खिलाफ मंत्री विजयशाह का पुतला दहन किया गया। ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुधीर ठाकुर ने बताया प्रदेश के मंत्री सत्ता के मदहोश में अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं। इस जनमानस को ठेस पहुंचती है। वहीं सेना पर टिप्पणी पर सेना का मनोबल गिरता है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं कही जा सकती है। इस पुतला दहन के अवसर पर कांग्रेस जनों ने कईअशोभनीय टिप्पणियां भी की। पुतला दहन के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीरसिंह ठाकुर नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, गजेंद्र सिंह चौधरी,राकेश चौधरी,नीरज चौधरी, पार्षद धर्मदास बेलवंशी, पूर्व पार्षद मोहन कहार, पार्षद भास्कर मांझी,शरद सारठे,इलियास ख़ान,अर्पित तिवारी,ऋषभ दीक्षित, करनपुर सरपंच आजादसिंह पटेल, सचिन श्रोती, वकील कार्तिक शर्मा,अंकित पटेल, वकील जयभानुसिंह चंदेल,इरफान ख़ान, धर्मेश ठाकुर,आकाश चौरसिया,शरद सराठे, गणेश अहिरवार,सैंडी सराठे,विकास रघुवंशी, उमेश आरसे आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मुलताई के घाटबिरोली में मिला युवक का शव

पुलिस शिनाख्ती में जुटी, पीएम रिपोर्ट से होगा खुलासा

बैतूल। शुक्रवार को मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम घाटबिरोली में एक अज्ञात युवक का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर दुनावा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। मृतक केवल अंडरगार्मेंट पहने हुए था, जिसमें नीली चड्डी और सफेद बनियान शामिल थी। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार के अनुसार, शव गांव के समीप एक सुनसान स्थान पर पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में शव चार से पांच दिन पुराना प्रतीत हो रहा है, जिससे आशंका है कि युवक की मौत कुछ दिन पहले हुई होगी। दुनावा चौकी पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई की और मर्ग कायम किया। शव को नगर पालिका के वाहन से मुलताई के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उसे पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी में सुरक्षित रखा गया है। एसआई सरयाम ने बताया कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्ट्म रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल मृतक के शरीर पर किसी स्पष्ट चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है और पड़ोसी गांवों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। थाना प्रभारी ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के लापता होने की सूचना हो या मृतक के संबंध में कोई भी जानकारी मिले, तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या दुनावा चौकी से संपर्क करें।

भारत में आज भी छत्रपति शिवाजी की कहानियां गूंजती हैं

धूमधाम से मनाई शिवाजी जयंती

बैतूल। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर शाम को शिवाजी चौक पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के समक्ष सैंकड़ों दीप प्रज्वलित किए गए साथ ही पुष्प वर्षा की गई। इस मौके वरिष्ठ समाजसेवी बीआर खंडागरे ने बताया कि एक वीर मराठा योद्धा जिसने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। अनगिनत लड़ाइयां लड़, ढेरों बार मुगलों को हराकर सैकड़ों किले फतह किए। इसी दिन उस शिवाजी का जन्म हुआ था जिसे फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। शिवाजी ये बस एक नाम नहीं, इतिहास के पन्नों में दर्ज पूरी गाथा है। युद्धनीति, वीरता और मराठा साम्राज्य की गाथा। छत्रपति शिवाजी महाराज वो नाम है, जो भारत के कोने-कोने में बसा ही है। भारत में आज भी शिवाजी की कहानियां गूंजती हैं। बाबा माकोड़े ने कहा कि शिवाजी महाराज ऐतिहासिक कहानी उस मराठा योद्धा की है जिसने मुगलों को इतनी बार हराया, इतने वार किए कि कई मुगल शासक तो उनके नाम से भी थर-थर कांपते थे। शिवाजी की नीतियां हमेशा किसानों और महिलाओं के पक्ष में होती थीं। कार्यक्रम का संचालन सरिता राठौर ने और आभार दिनेश मस्की, ने व्यक्त किया। इस अवसर पर दीपक राठौर, डॉ.एनआर साबले, रवि माकोड़े, तपन मालवीय, कृष्णा वागद्रे, गोपाल साहू, भगवत चढ़ोकार, मधु मस्की, नरेन्द्र गावंडे, वसंत वागद्रे, मुन्ना मानकर, केआर देशमुख, बीआर गलफट, संगीता देशमुख, साक्षी शर्मा, सेवंती माकोड़े, अशोक धोनी, कृष्णा वागद्रे आदि मौजूद थे।

प्रेस्टीज इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च,में 'कलर्स ऑफ इंडिया' थीम पर तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन

देवास । प्रेस्टीज इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (PIMR), देवास में विद्यार्थियों के लिए वार्षिक सांस्कृतिक समारोह 'उत्सव' का आयोजन 26 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ किया जा रहा है। इस वर्ष उत्सव की थीम 'कलर्स ऑफ इंडिया' रखी गई है, जो भारत की समृद्ध विविधता, परंपराओं एवं सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाती है। उत्सव के आयोजन की जानकारी देने एवं विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से 20 फरवरी 2026 को संस्थान के एट्रियम में डैंगलर लॉन्चिंग समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा विभिन्न आयोजनों की विस्तृत प्रस्तुति दी गई तथा उनसे संबंधित नियम एवं शर्तों की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, संगीत की धुनों पर नृत्य किया तथा सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के प्रति अत्यधिक उत्साह एवं ऊर्जा का प्रदर्शन किया। तीन दिनों तक चलने वाले इस सांस्कृतिक उत्सव में रंगोली प्रतियोगिता, बॉलीवुड के रंग, गायन एवं नृत्य प्रतियोगिताएं, ऐड-मैड शो, बॉलीवुड एंड बिज़नेस क्विज़, ट्रेडिशनल डे, PIMR देवास हाट, फैशन शो, रील मेकिंग एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता सहित अनेक सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इन आयोजनों का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। इस अवसर पर संस्थान की निदेशक प्रो. डॉ. आशिमा जोशी ने कहा कि उत्सव विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षा शिक्षण से आगे बढ़कर अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विद्यार्थी शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार वे सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियों में भी समान रूप से प्रतिभाशाली हैं। इसी उद्देश्य से संस्थान विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं को निखारने एवं प्रस्तुत करने हेतु एक सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं तथा उनमें उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इस सांस्कृतिक उत्सव के माध्यम से संस्थान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता एवं आत्मविश्वास को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का अवसर प्रदान करेगा। यह तीन दिवसीय उत्सव विद्यार्थियों के लिए एक यादगार अनुभव सिद्ध होगा। उक्त जानकारी कार्यक्रम समन्वयक सुश्री अर्चना राजपूत द्वारा दी गई।

12वीं के 2619 विद्यार्थियों ने 53 केंद्रों पर दी परीक्षा

बैतूल। माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा-2026 के तहत शुक्रवार को जिले में कक्षा 12वीं का एनएसक्यूएफ विषय का प्रश्नपत्र शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र वरकड़े ने बताया कि 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जिनमें कुल 2650 परीक्षार्थी दर्ज थे। इनमें से 2619 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 31 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने 7 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हुई।

बस स्टैंड पर पुतला दहन को लेकर हंगामा

कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में आधे घंटे तक खींचतान, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

बैतूल /मुलताई। बस स्टैंड पर कांग्रेस एवं पुलिस के बीच उसे वक्त तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला दहन का प्रयास कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच करीब आधे घंटे तक जोरदार खींचतान और झूमाझटकी हुई। अंततः पुलिस पुतला अपने कब्जे में लेकर चली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरुण यादव और प्रदेश कांग्रेस

कमेटी सदस्य संजय यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में बस स्टैंड पहुंचे थे। कार्यकर्ता भारत-अमेरिका ट्रेड डील, मनरेगा में बदलाव, नेता प्रतिपक्ष पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी और प्रदेश के तीन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस से झड़प के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में लगाए गंभीर आरोप ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील देश की कृषि व्यवस्था पर सीधा आघात है। इससे छोटे, सीमांत और मध्यम किसान तथा व्यापारी असमान प्रतिस्पर्धा में फंस जाएंगे और देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर होगी। मनरेगा के नाम और नियमों में बदलाव को कांग्रेस ने गरीब विरोधी कदम बताया। पार्टी का आरोप है कि इससे कामगारों के अधिकार प्रभावित होंगे।

मंत्रियों के इस्तीफे की मांग - ज्ञापन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी का भी विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही कफ सिरप से हुई मौतों, सेना अधिकारी एवं महिलाओं पर कथित अभद्र टिप्पणी और दूषित जलप्रदाय से हुई मौतों के मामलों में संबंधित मंत्रियों-राजेंद्र शुक्ला, विजय शाह और कैलाश विजयवर्गीय-के इस्तीफे की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में अरुण यादव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय यादव, प्रहलाद सिंह ठाकुर, सुमित शिवहरे ,किशोर सिंह परिहार, लोकेश यादव, राजू पवार दुनावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, धनराज पवार ,नितेश साहू, सुमित शिवहरे, पिंटू ठाकरे जीवन डोंगरे, लोकेश यादव, रितेश शर्मा,आशीष सोनी, कपिल खंडेलवाल, प्रकाश सेवतकर, जीवन डोंगरदिऐ, पिंटू ठाकरे, महेश नागले एवं अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सारणी में ईसीएचएस कक्ष का शुभारंभ, पूर्व सैनिकों को मिलेगी नियमित स्वास्थ्य सुविधा

बैतूल। रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व सैनिकों को प्रदान किए जाने वाले ईसीएचएस स्वास्थ्य लाभ अब और सुलभ हो गए हैं। चिकित्सालय, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी परिसर में शुक्रवार को ईसीएचएस कक्ष का उद्घाटन मुख्य अभियंता श्री सुशील कुमार लिल्होरे की उपस्थिति में किया गया। अब तक पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए महीने में एक बार दूरस्थ स्थान पर आयोजित मोबाइल क्लिनिक का सहारा लेना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत अब वायु सेना स्टेशन आमला की ईसीएचएस मोबाइल क्लिनिक प्रतिमाह सीधे सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी परिसर में संचालित होगी। ईसीएचएस मोबाइल क्लिनिक में एम्बुलेंस, चिकित्सक, सहयोगी स्टाफ तथा आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था रहेगी। इस पहल से क्षेत्र के पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें नियमित चिकित्सकीय परामर्श और निःशुल्क दवाइयाँ अपने निवास क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। इस अवसर पर कैप्टन आई एन सुमीत सिंह से.नि., जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बैतूल, अतिरिक्त एडिशनल चीफ इंजीनियर राजीव गुप्ता, यूनिट प्रभारी एनएस सिंह, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. विजय कुमार रघुवंशी, ईसीएचएस डॉ. संगीता पंवार सहित पूर्व सैनिक एवं स्टाफ उपस्थित रहे।

24 घंटे में साइबर अपराध के 11 प्रकरण दर्ज

केवाईसी अपडेट, ऐप डाउनलोड कराकर धोखाधड़ी की

बैतूल। बैतूल पुलिस ने जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देश पर बीते 24 घंटे के भीतर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में साइबर अपराध के 11 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ई-जीरो एफआईआर प्रणाली के तहत कुल 17 प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की जांच के लिए संबंधित थानों को भेजे गए हैं। हाल ही में सामने आए साइबर अपराधों में कई तरह की ठगी शामिल है। इनमें बैंक या केवाईसी अपडेट के नाम पर ओटीपी और बैंक विवरण लेकर धोखाधड़ी, रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड कराकर खाते से राशि निकालना, सोशल मीडिया पर लाइक और रिव्यू के बहाने निवेश ठगी, तथा व्हाट्सएप निवेश या शेयर ट्रेडिंग ग्रुप के जरिए उच्च रिटर्न का लालच देना प्रमुख हैं। इसके अलावा, बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर भुगतान कराना, ओएलएक्स या अन्य ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पर क्यूआर कोड स्कैन कराकर ठगी करना, फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से कॉल कर बैंक जानकारी लेना और लॉटरी या इनाम के नाम पर शुल्क मांगने जैसे मामले भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी, सीवीवी, एटीएम पिन या बैंक विवरण साझा न करें। किसी भी अज्ञात लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड करने से बचें और रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल न करें। किसी भी ठगी या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या पर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

ताप्ती सरोवर स्लूज गेट एवं शनि तालाब सौंदर्यीकरण की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण

42 लाख रुपये की लागत से होगा नवीनीकरण कार्य

बैतूल/मुलताई। धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी मुलताई की प्रमुख आस्था स्थली ताप्ती सरोवर और शनि तालाब के स्लूज गेट मरम्मत तथा सौंदर्यकरण कार्य की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब शीघ्र ही ताप्ती सरोवर के स्लूज गेट के नवीनीकरण और शनि तालाब के घाटों के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। भाजपा मीडिया प्रभारी रामचरण मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरवासी लंबे समय से क्षतिग्रस्त स्लूज गेट से हो रहे जल रिसाव और शनि सरोवर के घाटों की बिगड़ती स्थिति के सुधार की मांग कर रहे थे। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विधायक चंद्रशेखर देशमुख के प्रयासों से मुख्यमंत्री विशेष निधि से कुल 42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। नगर पालिका द्वारा पूर्व में भी स्लूज गेट निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन किसी ठेकेदार ने रुचि नहीं दिखाई

थी। दूसरी निविदा प्रक्रिया के बाद यह कार्य सतना निवासी अरुण प्रताप सिंह को सौंपा गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, सरोवर का जलस्तर घटते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इन कार्यों के पूर्ण होने से नगर की जल संरचना सुदृढ़ होगी तथा धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गढ़ेकर, सभापति डॉ. जी.ए. बारस्कर, मंडल अध्यक्ष गणेश साहू, मंडल महामंत्री राघवेंद्र रघुवंशी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय से यह मांग विधायक के समक्ष रखी जा रही थी।

इनका कहना है - ताप्ती सरोवर के स्लूज गेट एवं शनि तालाब के सौंदर्यकरण की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। गेट निर्माण का ठेका अरुण प्रताप सिंह, सतना को दिया गया है। जलस्तर कम होते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

- महेश शर्मा, उपयंत्री, नगर पालिका मुलताई

फुटपाथ की जगह बनाई जा रही नाली, बिना पोल हटाए कर दिया सड़क निर्माण

नपा की लापरवाही, हादसों का कारण बन रहे निर्माण कार्य

बैतूल/आमला। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से नपा के जिम्मेदारों की कथित लापरवाही और भर्राशाही के कई प्रकरण सामने आ चुके हैं, उससे शहर में ज्यादातर जगहों पर अव्यवस्थाएं और असुविधा होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कई जगहों पर नगरपालिका द्वारा किए जा रहे निर्माण से केवल लोगों को असुविधा और अव्यवस्थाएं ही नहीं हो रही है, बल्कि नगरपालिका के जिम्मेदारों की कारगुजारियों से दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है, या इसे सीधे तौर पर कहें तो नगर पालिका तकनीकी विभाग की लापरवाही से शहर में लोगों की जान भी जा सकती है। यहां हैरानी इस बात की है कि आखिर हादसों को निमंत्रण देते इस तरह की पुल, पुलिया, सडक़ बनाकर आखिर नगरपालिका के जिम्मेदार क्या करना चाहते हैं और उस पर सबसे बड़ा सवाल तो पूरी परिषद पर है कि इस तरह की अदूरदर्शिता और दुर्घटना को आमंत्रित करते इस तरह के निर्माण के बाद भी परिषद कर क्या रही है।

मोक्षधाम जाने वाले मार्ग पर हादसों वाली पुलिया -यहां सबसे पहले मोक्षधाम मार्ग पंचवटी हनुमान मंदिर के पीछे बीते वर्ष बनाई गई पुलिया की बात करें तो यहां बनाई गई एक पुलिया प्रतिदिन ही किसी बड़े हादसे को आमंत्रित कर रही है। इस पुलिया को जिस तरह से बनाया गया है, उसे देखकर कोई भी कह देगा कि ये पुलिया किसी अनाड़ी या फिर किसी बच्चों ने खेल के दौरान इस पुलिया का निर्माण किया होगा। जैसा कि हमें यहां के गणेश पवार, गुड्डू वर्मा,

हितेश सोनी सहित अन्य कई लोगों ने बताया है कि यहां मोक्षधाम वाली सडक़ से गुजरते समय हमेशा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। इसके अलावा यहां जिस तरह से पुलिया का निर्माण हुआ है। उस पर लोगों ने जिम्मेदारों पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करने की मांग भी की है।

मंगल भवन इलाके में बिजली का पोल हटाए बिना बनाई सडक़ - शहर के मंगल भवन इलाके में यहां तो नपा के जिम्मेदारों ने इंजीनियरिंग का बेहद अजीबोगरीब नमूना पेश किया है यहां बिजली का पोल हटाए बिना ही नगर पालिका ने सडक़ बना दी है, यहां भी लगातार हादसे हो रहे हैं, इलाके के लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, किंतु जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इधर शहर के बस स्टैंड इलाके में यहां नपा एक बड़ी नाली का निर्माण कर रही है। लोगों ने बताया है कि नगर पालिका नाली का निर्माण फुटपाथ की जगह पर कर रही है, जैसा कि यहां के लोगों ने बताया है कि अगर फुटपाथ की जगह पर नाली बनेगी तो शहर का मुख्य मार्ग सकरा हो जाएगा, अभी यहां पर डिवाइडर भी लगना है, ऐसे में अगर सडक़ संकरी होगी तो फिर निश्चित ही यहां हादसों को रोका नहीं जा सकता है। इस मौके पर यहां के कई लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि फुटपाथ की जगह पर सडक़ बनाने के पीछे किसी खास लोगों पर नगर पालिका मेहरबानी कर रही है, या फिर इस पूरे प्रकरण में कहीं सौदेबाजी भी हुई है।

इनका कहना है- मोक्षधाम वाले मार्ग पर शिकायत के बाद यहां एस्टीमेट बनाया गया है जल्दी ही यहां सुधार कर दिया जाएगा, इसके अलावा फुटपाथ वाली जगह पर नाली निर्माण के काम को फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोका जा रहा है।

- सुभाष शर्मा, सब इंजीनियर, नपा आमला

संक्षिप्त समाचार

संकट की घड़ी में बना सहारा: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भरत सिंह को मिले 2 लाख रुपये

विदिशा (निप्र)। कभी-कभी जीवन में अचानक आई विपत्ति पूरे परिवार को असहाय बना देती है, लेकिन शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं ऐसे कठिन समय में उम्मीद की किरण बनकर सामने आती हैं। ऐसा ही अनुभव गंजबासौदा निवासी भरत सिंह रघुवंशी के जीवन में देखने को मिला। गंजबासौदा के वार्ड क्रमांक 14, शिवनगर निवासी भरत सिंह रघुवंशी की पत्नी स्वर्गीय कविता रघुवंशी का दुखद निधन एक दुर्घटना में हो गया था। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया था। लेकिन स्वर्गीय कविता रघुवंशी के बैंक खाते से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जुड़ी होने के कारण परिवार को बड़ी राहत मिली। भरत सिंह रघुवंशी ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए दावा प्रस्तुत किया। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गंजबासौदा शाखा के माध्यम से 11 फरवरी 2022 को 2 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान उन्हें प्राप्त हुआ। बीमा राशि मिलने से भरत सिंह को आर्थिक संबल मिला और कठिन समय में परिवार को संभालने में मदद मिली। भरत सिंह ने बताया कि उन्हें इस योजना के महत्व का पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन आज यह योजना उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हुई है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि छोटी सी प्रीमियम राशि से जुड़ी बीमा योजना भी संकट की घड़ी में परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। यह योजना विशेष रूप से आमजन और कम आय वर्ग के परिवारों के लिए सुरक्षा कवच बनकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

नर्मदापुरम में निःशुल्क आयुर्वेद एनोरेक्टल चिकित्सा शिविर सम्पन्न

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के तत्वावधान में शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, नर्मदापुरम में एक दिवसीय निःशुल्क एनोरेक्टल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डॉ. एस.पी. वर्मा संभागीय अधिकारी, अनॉर्कटल सर्जन डॉ. राम सिन्हा एवं जिला आयुष अधिकारी डॉ. एस.आर. करोंजिया की उपस्थिति में भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पार्पित कर किया गया। शिविर में अर्श , भगंदर , परिकार्तिका एवं अन्य गुदगत रोगों से पीड़ित 164 मरीजों की जांच की गई। विशेषज्ञ टीम में पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान, भोपाल से वरिष्ठ एनोरेक्टल सर्जन डॉ. राम सिन्हा, पीजी स्कॉलर डॉ. रवीन्द्र पाटिल, डॉ. गुंजन, डॉ. सोनाली एवं डॉ. शुभांगी शामिल थीं। जांच के बाद 98 मरीजों को क्षारसूत्र शल्यकर्म के लिए चयनित किया गया, जिनकी निःशुल्क सर्जरी 23 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान, भोपाल में की जाएगी। इन मरीजों को 22 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक भर्ती होकर उपचार प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है। शिविर का निरीक्षण संभागीय आयुष अधिकारी डॉ. एस.पी. वर्मा ने किया। जिला आयुष अधिकारी डॉ. एस.आर. करोंजिया के मार्गदर्शन में शिविर नोडल अधिकारी डॉ. ए.के. पुष्कर, डॉ. सविता पुष्कर, डॉ. ललिता उइके, डॉ. मिथिलेश उइके, डॉ. संदीप रघुवंशी तथा पैरामेडिकल स्टाफ ने सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जिले में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करेगी स्व-सहायता समूह की महिलाऐं

हरदा (निप्र)। म.प्र.डे. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला हरदा अंतर्गत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हरदा में सोमवार को आजीविका स्व-सहायता समूहों को जैविक उत्पाद निर्माण, जैविक खेती व मार्केट लिंकेज के संबंध में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा, जैविक उत्पाद प्रसंस्करण की समझ विकसित करना एवं मार्केट उपलब्ध कराने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। इस कार्यक्रम में आजीविका स्व-सहायता समूह के तीनो विकासखंडों से अलग-अलग ग्रामों के अलग-अलग स्व-सहायता समूहों से 40 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यशाला में कृषि सखी, बीज सखी, पशु सखी एवं जैविक खेती करने हेतु इच्छुक किसान ने भाग लिया। जिले के मास्ट्रर ट्रेनर श्री जयनारायण राय द्वारा इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली जोसेफ, वरिष्ठ कृषि विज्ञानिक डॉ. संध्या मुरे, कृषि वैज्ञानिक डॉ. ओ.पी. भारती, उद्यानिकी विभाग से श्री योगेश तिवारी, आरसेटी प्रमुख श्री दिनेश शाक्या व श्री सुरेश धनगर, आजीविका मिशन से श्री राधेश्याम जाट, श्री शैलू सिंह चन्देल एवं श्री अभिजीत मिश्रा तथा श्री देवीसिंह तेकाम भी उपस्थित थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती जोसेफ ने उपस्थित प्रतिभागियो से जैविक खेती पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान जैविक खेती के लाभ/हानि एवं प्रशासनिक स्तर पर किये जा रहे प्रयास पर चर्चा की गई एवं सभी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जैविक खेती पर स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को मार्गदर्शन दिया गया तथा शासन द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं के संबंध में उपस्थित किसानों को विस्तार से जानकारी दी।

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा 76 आवेदनकर्ताओं की समस्या का किया गया समाधान

कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर विभिन्न विभागों ने की प्रभावी कार्रवाई

नर्मदापुरम (निप्र)। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाली समस्याओं का समाधान प्रशासन द्वारा सतत रूप से किया जा रहा है। गत सप्ताहों में प्राप्त हुई शिकायतों के निराकरण में जिला प्रशासन द्वारा उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए 81 समस्याओं का निराकरण किया गया। उक्त समस्याओं में विभिन्न प्रकार की समस्या जैसे राशि भुगतान, शासकीय योजनाओं का लाभ, अवैध अतिक्रमण सहित अन्य समस्याएं सम्मिलित रही। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देश अनुसार अधिकारियों द्वारा समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उनका निराकरण। समस्याओं का निराकरण होने के पश्चात संबंधित आवेदनकर्ताओं ने बताया कि किस प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों एवं संबंधित विभागों द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें राहत पहुंचाई। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित निराकरण प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम तारारोड़ा के एक युवक द्वारा जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि एक नशा मुक्ति केंद्र द्वारा उससे 21 हजार रुपए की राशि जमा कराई जा रही है, जबकि निर्धारित राशि 12 हजार रुपए है। आवेदन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा संबंधित नशा मुक्ति संस्था से प्रकरण की जांच कराई गई। जांच उपरांत संस्था को निर्देशित किया गया कि युवक से 21 हजार रुपए के स्थान पर 12 हजार रुपए ही लिए जाएं। प्रशासन की पहल पर राशि संशोधित कराई गई तथा युवक को विधिवत डिस्चार्ज भी कराया गया।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत खरखेड़ी निवासी लक्ष्मी द्वारा जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि हाट बाजार निर्माण कार्य एवं पिचिंग वॉल का कार्य तो किया गया है, किंतु पिचिंग वॉल के पास सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं होने से नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा संबंधित आरईएस विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उक्त संबंध में आवेदनकर्ता ने बताया कि उनकी शिकायत का शांतिपूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण कर दिया गया है तथा विभाग द्वारा अनुबंधित कार्य पूर्ण कराए गए। एक अन्य आवेदन पर कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग द्वारा आवेदनकर्ता श्री निखिल राजपूत की समस्या का समाधान किया गया। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर संज्ञान लेते हुए श्रम विभाग ने उनके पिता श्री पर्वत सिंह राजपूत का मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना के अंतर्गत विधिवत पंजीयन कराया तथा संबंधित पंजीयन कोड जारी किया। शिकायतकर्ता राम चरण सिंह द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि उन्होंने इटारसी स्थित एक कॉलोनी में प्लॉट बुक करते समय कॉलोनी मालिक को एक लाख रुपए की राशि का भुगतान किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, कॉलोनी के प्रचार-प्रसार के दौरान कॉलोनी मालिक द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। इस कारण उन्होंने प्लॉट क्रय नहीं करने का निर्णय लिया तथा बुकिंग के समय दी गई एक लाख रुपए की राशि वापस करने के लिए कॉलोनी मालिक से अनुरोध किया, किंतु राशि वापस नहीं की गई। इस संबंध में उन्होंने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा शिकायतकर्ता एवं कॉलोनी मालिक को तहसील कार्यालय में समक्ष में बुलाकर आपसी सहमति से कॉलोनी मालिक द्वारा शिकायतकर्ता को एक लाख रुपए की राशि चेक के माध्यम से तत्काल प्रदान की गई। इसी प्रकार जनसुनवाई के दौरान प्राप्त हुई अन्य समस्याओं का निराकरण भी संबंधित अधिकारियों एवं विभागों द्वारा करवाया गया।

मंगलवार को भी जनसुनवाई में ग्राम पथोड़ी निवासी शंकर लाल ने जल निकासी की उचित व्यवस्था ना होने के कारण दूषित जल भराव की समस्या से अवगत कराया। जिस पर कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रबंधक को जल निकासी के उचित व्यवस्था कर समस्या का शीघ्र निराकरण करने के निर्देशित किया। इसी प्रकार नर्मदापुरम निवासी नीरज बरगले ने निजी भूमि पर लोहे की सीढ़ी बनाकर अस्थाई अतिक्रमण कर लिया है, उन्होंने अतिक्रमण शीघ्र हटाने के लिए आवेदन दिया। जनसुनवाई मे आए नर्मदापुरम निवासी योगेश कुमार साहू ने नगर मे स्थित भोपाल तिराहे एव खोजनपुर ग्वालटोली मे मृत पशु एवं बदबूदार कचरा फेका जा रहा हैं, जिससे विषैले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है जो संक्रमण और श्वास रोग का कारण बन रहा हैं। जिस पर कलेक्टर ने नगर पालिका अधिकारी को फैल रहे कचरे का उचित प्रबंधन करने को लेकर निर्देशित किया।

एमएसएमई रैम्प योजना के तहत बैतूल में जागरूकता कार्यशाला आयोजित

बैतूल (निप्र)। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई के सशक्तिकरण, गुणवत्ता सुधार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार की रेजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना के अंतर्गत बैतूल जिले के शासकीय एकलव्य महिला आई टी आई कोसमी में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उद्योग संघ अध्यक्ष श्री ब्रज आशीष पांडे, महिला आईटीआई प्राचार्य श्री रेवाशंकर पंडाग्रे रहे। विशिष्ट अतिथियों में सहायक प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्री प्रवीण खवसे, रैम्प कंसलटेंट श्री रवीश कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक श्री प्रवीण खौसी द्वारा किया गया। कार्यशाला की शुरुआत में सहायक प्रबंधक द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा मध्य प्रदेश शासन की नवीन एमएसएमई नीति-2025 के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। रैम्प कंसलटेंट श्री रवीश कुमार ने रैम्प योजना के लक्ष्यों, लाभों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर श्री ब्रज आशीष पांडे जी ने जेड-लीन के अपने अनुभव साझा करते हुए उद्यमियों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान गुणवत्ता विशेषज्ञ डॉ प्रवीण कुमार जैन ने जेड योजना, ईएसजी पर प्रस्तुति देते हुए गुणवत्ता सुधार, सर्टिफिकेशन प्रक्रिया एवं इसके लाभों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेड योजना अपनाकर उद्योग उत्पादन गुणवत्ता में सुधार कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। आरईसीपी विशेषज्ञ श्री फवाद खान द्वारा आरईसीपी प्रबंधन की अवधारणा एवं इसके लाभों पर विशेष जानकारी दी। कार्यशाला में एमएसएमई क्षेत्र के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की उपयोगिता पर चर्चा की गई, जिस पर उपस्थित उद्यमियों ने सरकारी योजनाओं से जुड़ने में गहरी रुचि व्यक्त की। कार्यशाला के समापन पर उद्यमियों ने रैम्प एवं जेड योजनाओं को अपनाकर अपने उद्योगों के विकास, विस्तार एवं गुणवत्ता उन्नयन हेतु संकल्प व्यक्त किया।

आनंदपुर लटेरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण संपन्न, महिला सुरक्षा व बाल संरक्षण पर दिया गया विशेष मार्गदर्शन

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा सतगुरु सेवा ट्रस्ट, आनंदपुर लटेरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विभाग की अधिकारी श्रीमती लोढ़ा ने बताया है कि प्रशिक्षण में जिले की 150 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला सुरक्षा, जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम एवं बाल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक एवं सशक्त बनाना था, ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा घरेलू हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की पहचान एवं रोकथाम के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र में पोषण ट्रैकर ऐप, आभा आईडी एवं अपार आईडी की उपयोगिता पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। पोषण ट्रैकर के माध्यम से बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण स्तर की निगरानी तथा डिजिटल सेवाओं से लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया समझाई गई। कार्यक्रम में सतगुरु सेवा ट्रस्ट के संचालक रविन्द्र जी सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के श्री आशीष यादव, श्री राजीव कॉल, श्री महेंद्र धाकड़, परियोजना प्रभारी श्रीमती कोलोडिया तिर्की एवं प्रशिक्षक श्री अरविंद मिश्रा उपस्थित रहे। सभी ने प्रशिक्षण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। अधिकारियों ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनकी सक्रिय भूमिका से महिला सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण को और अधिक मजबूती मिलेगी।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभिन्न विभागों की सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा कर शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश

रायसेन (निप्र)। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंचायत विभाग, कृषि विभाग और पीएचई विभाग की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की गई। उन्होंने विभागवार और अधिकारीवार लंबित सीएम हेल्पलाईन की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगामी दो दिवस में अधिक से अधिक शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराने के निर्देश दिए। बैठक में नवागत जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित रहे। अनुभागों से एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीईओ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने राजस्व विभाग की सीएम हेल्पलाईन की तहसीलवार समीक्षा करते हुए तहसीलदार बाड़ी, गौहरगंज तथा रायसेन की अधिक संख्या में सीएम हेल्पलाईन लंबित होने तथा निराकरण की गति संतोषजनक नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित तहसीलदारों को प्राथमिकता से सीएम हेल्पलाईन का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा के दौरान सीएमओ मण्डीदीप के पास 72 सीएम हेल्पलाईन शिकायतें लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की तथा कार्यप्रणाली में सुधार लाते हुए दो दिवस में शिकायतों का निराकरण कराने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य नगरीय निकायों में लंबित सीएम हेल्पलाईन की भी समीक्षा कर सीएमओ को निराकरण संबंधी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान जनपद सीईओ गैरतगंज, जनपद सीईओ बेगमगंज और जनपद सीईओ औबेदुल्लागंज सहित अन्य जनपद पंचायतों के सीईओ से सीएम हेल्पलाईन निराकरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश दिए। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों में लंबित सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा करते हुए शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया। बैठक में नवागत जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखण्डों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ, बीएमओ सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में गठित की गई है जिला स्तरीय उपार्जन समिति

रायसेन (निप्र)। जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की समस्त प्रक्रिया पंजीयन, पर्यवेक्षण, स्कंध की गुणवत्ता नीति के अंतर्गत आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उपार्जन समिति गठित की गई है। इस समिति में जिला लीड बैंक अधिकारी, उप संचालक कृषि, उपायुक्त सहकारिता, जिला सूचना अधिकारी, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायसेन, जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड रायसेन, जिला प्रबंधक मप्र वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन रायसेन, जिला प्रबंधक मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, अधीक्षक भू-अभिलेख तथा सचिव कृषि उपज मंडी रायसेन को सदस्य बनाया गया है।

मातृ मृत्यु प्रकरणों की समीक्षा, स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

विदिशा (निप्र)। जिले में मातृ मृत्यु दर को कम करने एवं स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार की अध्यक्षता में मातृ मृत्यु प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस माह जिले में हुई सभी मातृ मृत्यु के मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डॉ. पुनीत माहेश्वरी एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। समीक्षा के दौरान मातृ मृत्यु के कारणों, उपचार के दौरान अपनाई गई प्रक्रियाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं तथा संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका का गहन विश्लेषण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि आशा कार्यकर्ता, एएनएम एवं स्वास्थ्य अमला क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग करें और गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि मातृ मृत्यु की घटनाओं को रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास जारी रखने की बात कही, जिससे सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा मिल सके।

एचपीवी टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित, सीएमएचओ ने दिए आवश्यक निर्देश

विदिशा (निप्र)। जिले में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में ग्यारसपुर एवं पीपलखेड़ा क्षेत्र के कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर एवं संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रभारी जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. हेमन्त पंचोली द्वारा उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को एचपीवी टीकाकरण की प्रक्रिया, पात्र हितग्राहियों की पहचान, टीकाकरण की तकनीक, टीके के सुरक्षित भंडारण तथा रिपोर्टिंग संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

सीएमएचओ डॉ. रामहित कुमार ने निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य कर्मी अपने-अपने क्षेत्र में पात्र किशोरियों एवं हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें समय पर टीकाकरण से लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि एचपीवी टीकाकरण महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रशिक्षण में टीकाकरण से संबंधित शंकाओं का समाधान भी किया गया तथा स्वास्थ्य कर्मियों को क्षेत्र में प्रभावी जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक हितग्राही इस महत्वपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम का लाभ ले सकें।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: 779 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना, जनप्रतिनिधियों ने दिखाई हरी झंडी

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 779 तीर्थ यात्री भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन से रवाना हुए। इस अवसर पर विदिशा रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया और उत्साहपूर्ण माहौल में उन्हें यात्रा के लिए विदाई दी गई।

फीता काटकर बोगी में प्रवेश

विदिशा विधायक श्री मुकेश टण्डन ने अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों को स्पेशल ट्रेन की बोगी में प्रवेश कराने हेतु फीता काटा और नारियल फोड़कर पूजा अर्चना की हैं कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन और विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा द्वारा विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने सभी तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी वर्षों पुरानी आस्था पूर्ण हो रही है। रेलवे स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं परिजनों द्वारा यात्रियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रियों में विशेष उत्साह देखने को मिला और उन्होंने शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रशासन द्वारा यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। यात्रा के दौरान भोजन, चिकित्सा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की निशुल्क यात्रा कराई जा रही है, जिससे उन्हें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है।गौरतलब हो कि जिले के सभी तीर्थ यात्रीगण अयोध्या में दर्शन उपरांत 23 फरवरी को वापस विदिशा पहुंचेंगे। इस अवसर पर विदिशा जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री वीर सिंह रघुवंशी, नटेरन जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती संगीता यशपाल रघुवंशी, एसडीएम श्री क्षितिज शर्मा समेत अन्य विभागो के अधिकारी व तीर्थयात्रा पर रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों के परिजन मौजूद रहे

भोपाल में संघ प्रचारक की एक्सीडेंट में मौत

● शादी समारोह में शामिल होकर गांव लौटते समय हादसा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के ईटखेड़ी इलाके में नेपानिया जोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार संघ प्रचारक और उनके साथी को टक्कर मार दी। हादसा गुरुवार शाम का है। इलाज के दौरान प्रचारक की तड़के मौत हो गई। उनके साथी की हालत नाजुक है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक दिनेश सिंह राजपूत पुत्र किशन सिंह राजपूत (55) ग्राम मेघराकलां बैरसिया के रहने वाले थे। वह परिचित की शादी समारोह में शामिल होने ईटखेड़ी आए थे। यहां से लौटते समय उनकी बाइक को नेपानिया जोड़ के पास अज्ञात वान ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दिनेश और उनके साथी समंदर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जहां दिनेश की मौत हो गई। समंदर की हालत नाजुक है।

तकनीक तभी सार्थक जब वह मानव हित में हो

हम एआई को सुशासन और सबके विकास के लिए अपनाएंगे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

● प्रदेश में एआई बेस्ड डेटा सेंटर की स्थापना के लिए निवेशक आमंत्रित, मप्र जल्द लांच करेगा स्टेट एआई मिशन

● मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में की इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सहभागिता

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कोई भी नई तकनीक तभी सार्थक है, जब वह मानवता के हित में अवसरों से भरपूर और कारगर हो। हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) को नवाचार के साथ सबके विकास, सामाजिक समरसता, सुशासन और देश-प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साधन के रूप में अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत आज डिजिटल परिवर्तनों को अपनाकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में एआई कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन उद्योग और प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एआई के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और आम नागरिक तक योजनाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय एकता और सामूहिक संकल्प का आह्वान करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। हम सब एकजुट होकर एआई के माध्यम से भारत को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एआई तकनीक हमारे लिए अवसर भी है और जिम्मेदारी भी। शीघ्र ही मध्यप्रदेश स्टेट एआई मिशन लांच करेगा, जो शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक अवसरों को तकनीक आधारित रूप में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम् में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 के समापन सत्र में सहभागिता की। उन्होंने भारत मंडपम् स्थित भोपाल मीडिया सेंटर में नेशनल मीडिया करेस्पांडेंट्स से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के भविष्य और इसके इस्तेमाल पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एआई से निर्भय होकर देश के हित में काम करने पर जोर दिया है। हमारी सरकार प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी चुनौतियों से उबरकर तेज गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें मध्यप्रदेश भी अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। मध्यप्रदेश, भारत का 5वां बड़ा राज्य है। राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में एआई की मदद से सही समय पर बीमारियों की पहचान और उनका निदान एवं सुदूर अंचलों तक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।

विजयवर्गीय ने सिंघार को औकात बताई फिर दुख जताया

कांग्रेस ने प्रदेशभर में किया प्रदर्शन, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुतले जलाए

भोपाल (नप्र)। नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को औकात बताने वाले बयान के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजयर्गीय का पुतला जलाने की कोशिश की। वहीं पुलिसकर्मी पुतला दहन से रोकने का प्रयास कर रहे थे।

इसे लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच छीना-छपटी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के साथ ही प्रदेश में कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुतले का दहन किया।

अदाणी का नाम लेने पर मंत्री ने जताई आपत्ति- विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार सिंगरोली में अडाणी की कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच तीखी बहस हो गई। इसी दौरान संसदीय कार्यमंत्री विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष से कह दिया औकात में रहो। चर्चा के दौरान सिंघार ने सरकार और अदाणी

के बीच समझौते का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई और कहा कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस परंपरा का पालन करने के निर्देश दिए।

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गलत जानकारी दे रहे हैं। इस पर उमंग सिंघार ने कहा कि वह हर बात प्रमाण के साथ करते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रमाण दे सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच बहस तेज होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी खड़े हो गए। सदन में कुछ समय तक हंगामा होता रहा और कार्यवाही प्रभावित हुई।

विधानसभा अध्यक्ष बोले- दोनों पक्षों को गुस्सा आ गया, यह अच्छा नहीं- 40 मिनट के अंतराल के बाद सदन की दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज दिन कुछ गरम-गरम सा है।तोमर ने कहा कि सदन के संचालन के लिए नियम और परंपरा का पालन जरूरी है।

आज दुर्भाग्य से थोड़ी सी असहज स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है, सदन का गौरव लगातार बढ़ता रहे, इस बात का प्रयत्न सभी पक्षों के सदस्यों को करना चाहिए।

तोमर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा कहते थे कि सदन में बात करते समय गुस्सा दिखना चाहिए, लेकिन गुस्सा आना नहीं चाहिए। लेकिन आज दोनों पक्षों को गुस्सा आ गया है, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत पहिए हैं। सभी से आग्रह करूंगा कि इस विषय का यही पटाक्षेप करें।

मंत्री विजयवर्गीय बोले-

अपने व्यवहार से अप्रसन्न, उमंग को प्यार करता हूं- संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे करीब 37 साल का राजनीतिक अनुभव है। आज मैं खुद अपने व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूं। जो जवाबदार पद पर बैठते हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, अगर वे संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो बाकी सदस्य कैसे करेंगे। आज पता नहीं कैसे हो गया, नेता प्रतिपक्ष ने मेरी ओर हाथों से इशारा किया, उमंग की बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा अलग थी, मैं उमंग को प्यार करता हूं। मैं अपने व्यवहार से दुखी हूं। इस पर हेमंत कटारे ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री को खेद व्यक्त करना चाहिए। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि अब कोई आगे ऐसा ना करे, इस बात का ध्यान रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने दुख व्यक्त किया है, यह पर्याप्त है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने पर्याप्त बातें कह दी हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो वह अपनी ओर से सबसे माफी मांग लेते हैं।

24 फरवरी को भोपाल आएंगे राहुल गांधी और खड़गे

ट्रेड डील के खिलाफ लड़ाई की एमपी से होगी शुरुआत, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा

भोपाल (नप्र)। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 24 फरवरी को भोपाल आएंगे, जानकारी के मुताबिक यहां किसानों से जुड़ा एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होगा। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश से की जाएगी।

एमपी से आंदोलन की शुरूआत होगी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस समझौते से सोयाबीन, कपास और मक्का उत्पादक किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने बताया कि किसानों के हितों की इस लड़ाई को राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में देशभर में आगे बढ़ाया जाएगा, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी।

धीरेंद्र शास्त्री के बयान को रामेश्वर शर्मा का समर्थन

बोले- बेटियों को जागरूक करना जरूरी, लव जिहाद से सतर्क रहने की दी सलाह

भोपाल (नप्र)। ग्वालियर के डबरा में नवग्रह पीठ के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान धीरेंद्र शास्त्री द्वारा दिए गए बयान का भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थन किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि तुम काली बनो, दुर्गा बनो, बुर्के वाली मत बनो जैसे शब्द यदि धीरेंद्र शास्त्री ने कहे हैं, तो वे उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने इसे स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि समाज में बेटियों के भीतर जागरूकता लाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि बेटियों को कथित 'लव जिहाद' जैसे मामलों से सावधान रहने की जरूरत है। उनके अनुसार कुछ लोग पहचान छिपाकर या नाम बदलकर युवतियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। कभी माथे पर टीका लगाते हैं, कभी हाथ में कलावा बांधते हैं और बाद में उनका शोषण करते हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भारत की बेटियां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और काली का स्वरूप हैं तथा भारतीय संस्कृति की पहचान हैं। उन्होंने बेटियों से सजग रहने और अपनी परंपरा व संस्कारों को बनाए रखने का आग्रह किया।

एक लाख 81 हजार से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये कराया पंजीयन : मंत्री श्री राजपूत

भोपाल (नप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अब तक एक लाख 81 हजार 793 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। पंजीयन की कार्यवाही 7 मार्च तक जारी रहेगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि निर्धारित समय में पंजीयन जरूर करा लें। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। कुल 3186 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रूपये अधिक है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि अभी तक इंदौर संभाग में 27 हजार 175, उज्जैन में 73 हजार 398, ग्वालियर में 3358, चम्बल में 1449, जबलपुर में 12 हजार 342, नर्मदापुरम में 11 हजार 698, भोपाल में 41 हजार 268, रीवा में 3242, शहडोल में 726 और सागर संभाग में 7137 किसानों ने पंजीयन कराया है।

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है।
पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था- पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है।

भोपाल में हुआ पहली बार फेमिना मिस इंडिया-2026 का ग्रैंड फिनाले

धनुश्री चौहान बनीं विजेता, अब राष्ट्रीय मंच पर करेंगी प्रदेश का प्रतिनिधित्व

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के भोपाल में फेमिना मिस इंडिया-2026 का ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें सिवनी की धनुश्री चौहान विनर रहीं। यह आयोजन सस्टेनेबिलिटी-फर्स्ट, जीरो-वेस्ट इवेंट की थीम पर आधारित था। इसमें पूरे प्रदेश से चुनी गईं 16 प्रतिभागी ताज के लिए मुकाबला कर रही थीं। अब विजेता राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

पहली बार मध्यप्रदेश में स्टेट ग्रैंड फिनाले- फेमिना मिस इंडिया की 60 वर्षों से अधिक पुरानी विरासत रही है। इस मंच ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली कई हस्तियां दी हैं। वर्ष 2026 में पहली बार इसका स्टेट ग्रैंड फिनाले मध्यप्रदेश में आयोजित किया गया।

60 साल की लिगसी वाला फेमिना ब्रांड पहली बार भोपाल आया- फेमिना की सिटी डायरेक्टर अपेक्षा श्रीवास्तव ने बताया कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 60 साल की लिगसी वाला फेमिना ब्रांड पहली बार भोपाल में आया है। इतना ही नहीं, 19 फरवरी यानी आज फेमिना 2026 का फिनाले भी है।

यहां के विनर अब नेशनल फेमिना कंपटीशन में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगी। इस कंपटीशन के भोपाल में होने से न केवल राजधानी

बल्कि प्रदेश के अन्य शहरों के युवाओं को भी उनके घर के पास बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। यह पहली सीढ़ी है, जो उन्हें उसे रास्ते पर ले जाती है, जिस पर चलकर प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, हरनाज संधू जैसी बड़ी सेलिब्रिटी बनी।

इस बार रतलाम, शामगढ़, छिंदवाड़ा से भी पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया- अपेक्षा श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार इवेंट की सबसे खास बात यह है कि न केवल भोपाल और इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश के छोटे कस्बे और शहर जैसे रतलाम, शामगढ़, छिंदवाड़ा से कई पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके अलावा किसान की बेटी से लेकर अगल-अलग प्रोफाइल की बच्चे इस बार इस मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन्हें इसके लिए इस रूप में तैयार किया गया कि वो क्राउड को फेस बेहतर तरीके से करें, इंटरव्यू अच्छे से दे सकें, पब्लिक इवेंट में अपने हुनर को बेबाकी से प्रदर्शित कर सकें।

उन्होंने बताया कि अब राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे स्टेट लेवल प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता को स्टेट क्राउन प्रदान कर सकें। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। स्टेट से चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर जीतने के बाद ही क्राउन मिलता था।

तीन दिनी 'वनमाली कथा सम्मान समारोह' 24 फरवरी से

भोपाल। चौदहवां 'वनमाली कथा सम्मान समारोह' 2026 भोपाल में 24 से 26 फरवरी तक होगा। इस तीन दिनी समागम में वनमाली सृजन पीठ द्वारा स्थापित सम्मानों से प्रतिष्ठित साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। इस बार 'वनमाली कथाशीर्ष सम्मान' से सुप्रसिद्ध रचनाकार मृदुला गर्ग को तथा 'राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान' से वरिष्ठ कथाकार अलका सरावगी को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि ज्ञानपीठ विजेता ओडिया कथाकार प्रतिभा राय होंगी।

यह जानकारी प्रतिष्ठित साहित्यकार, शिक्षाविद एवं 'वनमाली सृजन पीठ' के अध्यक्ष संतोष चौबे ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि वनमालीजी प्रेमचंद की पीढ़ी के अनूठे रचनाकार थे, लेकिन उनके सृजन का उनके रहते समुचित मूल्यांकन नहीं हो सका। लेकिन अब हो रहा है। इसी संदर्भ में 'वनमाली सृजन विगत कई वर्षों से वनमालीजी की स्मृति में रचनाकारों को पुरस्कृत रही है। वनमाली सम्मान समारोह का चौदहवां साल है। इस बार 8 अलग अलग श्रेणियों में रचनाकारों को वनमाली कथा सम्मानों से अलंकृत किया जाएगा।

चौबेजी ने कहा कि तीन दिनी सम्मान समारोह 'विश्वरंग' के अंतर्गत वनमाली सृजन पीठ, रबीन्द्रनाथ टैगोर विवि, स्कोप ग्लोबल स्किल्स विवि तथा आईसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा 24, 25 व 26 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन स्कोप विवि तथा रबीन्द्रनाथ टैगोर विवि के सुरम्य परिसरों में आयोजित होगा। समारोह की शुरूआत लोकगायक पद्मश्री प्रह्लाद सिंह टिपाणिया के कबीर गायन से होगा।

पुरस्कृत विभूतियों की जानकारी देते हुए चौबेजी ने कहा कि इस बार 'वनमाली कथाशीर्ष सम्मान' से जानी मानी साहित्यकार मृदुला गर्ग को तथा 'राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान' से कथाकार अलका सरावगी को सम्मानित किया जाएगा। दोनों रचनाकारों को पुरस्कारस्वरूप शाल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं 1 1 लाख रू. की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। जबकि अन्य पुरस्कारों के तहत 51 51 हजार रू. की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वनमाली सृजन पीठ ने सम्मानों की श्रृंखला में इस बार से कथा अनुवाद को प्रमुखता से सम्मिलित किया है। पहली बार यह सम्मान अनुवाद को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दिलाने के लिए साहित्यकार, अनुवादक जितेन्द्र भाटिया को दिया जाएगा। वनमाली कथा आलोचना सम्मान' महेश दर्पण को, वनमाली कथा मप्र सम्मान वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष को, वनमाली युवा कथा सम्मान युवा कथाकार कुणालसिंह को, वनमाली कथेतर सम्मान अयोध्या के यतीन्द्र सिंह को प्रदान किया जाएगा। साहित्य क्षेत्र में डिजीटल माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहला 'वनमाली डिजीटल साहित्य अवदान सम्मान' अंजुम शर्मा को प्रदान किया जाएगा।

संतोष चौबे ने कहा कि नई सदी की नई रचनाशीलता को सम्यक एवं समुचित स्थान देने के उद्देश्य से प्रारंभ लोकतांत्रिक मूल्यों की समावेशी पत्रिका 'वनमाली कथा' के फरवरी अंक का लोकार्पण भी इसी समारोह में होगा। इसके अलावा तीनों दिन सम्मानित रचनाकारों का रचना पाठ, 'डिजीटल युग में शास्त्रीय संगीत रियाज से रील तक', 'डिजीटल युग में साहित्य पाठक परिवर्तन' और' नई प्रासंगिकताएं, समकालीन युवा कहानी की संवेदनाएं और सामाजिक 'जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श के विशेष सत्र भी आयोजित होंगे। इन सत्रों में प्रतिभा राय, मृदुला गर्ग, जितेन्द्र भाटिया,अलका सरावगी,महेश दर्पण,उर्मिला शिरीष, संतोष चौबे,लीलाधर मंडलोई, गीताश्री, यतीन्द्र मिश्र, कुणालसिंह, अंजुम शर्मा,अरूणेश शुक्ल, संजय शेफर्ड, कैफी हाशमी आदि की रचनात्मक भागीदारी होगी। सत्र संचालन विनय उपाध्याय,संगीता पाठक, विकास अवस्थी एवं विक्रांत भट्ट करेंगे। समारोह का संयोजन वनमाली सृजन पीठ की राष्ट्रीय संयोजक ज्योति रघुवंशी करेंगी। वनमाली कथा सम्मान के दूसरे दिन 25 फरवरी को रबीन्द्रनाथ टैगोर विवि के शारदा सभागार में संतोष चौबे की कहानी 'मगर शेक्सपियर को याद रखना' का नाट्य मंचन वरिष्ठ निर्देशक संजय मेहता के निर्देशन में होगा। इस अवसर पर टैगोर विवि के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यार्थी रंग संगीत की सांगीतिक प्रस्तुति देंगे।

पत्रकारवार्ता में मौजूद मुकेश वर्मा ने बताया कि सम्मानों के लिए चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है। इसके लिए आवेदन लेने की जगह रचनाकारों के सृजन कर्म का एक सुविज्ञ टीम वर्षभर आकलन करती है। उसी के आधार पर आम सहमति से पुरस्कार के लिए नाम तय होते हैं। पत्रकार वार्ता को विनय उपाध्याय तथा ज्योति रघुवंशी ने भी संबोधित किया।

उपनेता प्रतिपक्ष कटारे के इस्तीफे की सूचना

खड़गे को लिखा- परिवार और क्षेत्र की जनता को समय नहीं दे पा रहा

भोपाल (नप्र)। अटेर से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने की सूचना है। कटारे ने इस्तीफा पत्र में लिखा कि परिवार और क्षेत्र की जनता को पर्याप्त समय नहीं दे पाने के कारण वे यह जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं।

उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे पत्र में लिखा कि संगठन जिसे चाहे इस पद की जिम्मेदारी दे, वे पूर्ण सहयोग करेंगे। पार्टी ने उन्हें इस योग्य समझा, इसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे।

मैरिज एनिवर्सरी के दिन दिया इस्तीफा- हेमंत कटारे की आज मैरिज एनिवर्सरी है। वे शाम करीब 4 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही में मौजूद रहे थे, फिर अचानक बाहर आ गए।

20 हजार से अधिक वोटों से जीते थे

विधानसभा चुनाव 2023 में हेमंत कटारे ने बीजेपी से पूर्व मंत्री रहे अरविंद भदौरिया को 20228 वोटों से हराया था। वे पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के बेटे हैं। पहली बार अटेर सीट से 2013 में विधायक बने।